

नई दिल्ली
रविवार
13 सितंबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 10
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0
E-mail story@sadbhawna.today sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

गयाजी में 25 सितंबर से शुरु होगा पितृपक्ष मेला,...**पेज-05**

DELHIN/2014/58158

भाई आनंद के बेटों को बसपा में रहकर राजनीति...पेज-08

एक नजर

यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती का मतलब रूस के साथ सीधी जंग : पुतिन

नई दिल्ली/माँस्को,एजेंसी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों के सैनिकों की संभावित तैनाती को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय नाटो देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजते हैं, तो इसे रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव के रूप में देखा जाएगा। पुतिन ने यह बयान शुक्रवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया। रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे (आरटी) के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस यूरोपीय देशों को धमकी नहीं दे रहा है और न ही ऐसा करने की उसकी कोई योजना है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन में यूरोपीय नाटो देशों की सैन्य मौजूदगी संघर्ष को रूस और पश्चिम के बीच सीधे टकराव में बदल सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश यूक्रेन में सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। रूस पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि सुरक्षा गारंटी या शांति मिशन के नाम पर नाटो देशों की यूक्रेन में सैन्य तैनाती स्वीकार नहीं होगी। पुतिन ने यूरोप की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों के नेतृत्व की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के बाद विदेश नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसलों में यूरोपीय नेताओं ने कोई "सिस्टम से जुड़ी गलतियाँ" की, जिनका असर अब दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी नेतृत्व और वैश्विक अभिजात वर्ग को विश्वास हो गया था कि वे सत्ता और प्रभाव के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और उनसे गलतियां नहीं हो सकतीं।

जम्मू-कश्मीर में लश्कर से जुड़े 10 ठिकानों पर एनआईए का छापा

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संचालकों और उनके स्थानीय सहयोगियों से जुड़े सीमा पार आतंकी षड्यंत्र मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामुला और सोपोर में की गई। इस दौरान मामले से संबंधित आपतिजनक सामग्री जब्त की गई है। एनआईए के अनुसार, कार्रवाई का उद्देश्य लश्कर संचालकों और स्थानीय भूमिगत कार्यकर्ताओं के नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य जुटाना तथा घुसपैठ कर आए आतंकियों को ठिकाना, आवाजाही और अन्य रसद सलयता उपलब्ध कराने वालों की भूमिका का पता लगाना है। मामला मूल रूप से श्रीनगर के जकूरू थाने में 0024/2026 नंबर की प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया था। बाद में एनआईए ने इसे आरसी-02/2026/एनआईए/जेएमयू के रूप में फिर से दर्ज किया। मामले में गैरकायूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967, शस्त्र अधिनियम, 1959 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की संघदित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। जांच की शुरुआत 31 मार्च 2026 की देर रात नाके पर लश्कर से जुड़े एक स्थानीय भूमिगत कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। उसके कब्जे से एक हथगोला और ज़िदा कारकतूस बरामद किए गए थे।

आगे की जांच में षड्यंत्र से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई और स्थानीय सहायता नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की गई।

संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स के जरिए प्रभावी भूमिका निभाए भारत: कांग्रेस

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि भारत को ब्रिक्स के माध्यम से समान और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री एवं कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष सलमान खुशींद ने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत को ब्रिक्स के भीतर नैतिक नेतृत्व और राजनीतिक स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए तथा राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के साथ नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



गयाजी में 25 सितंबर से शुरु होगा पितृपक्ष मेला,...**पेज-05**

DELHIN/2014/58158

भाई आनंद के बेटों को बसपा में रहकर राजनीति...पेज-08

ब्रिक्स देशों ने साझा घोषणापत्र में सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शनिवार को 140 बिंदुओं वाला नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग करते हुए वैश्विक संस्थाओं में सुधार, एकतरफा दंडात्मक व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में असमानता दूर करने और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर महिला एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की जरूरत पर जोर दिया गया। वीटो पावर वाले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत तथा ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिक्स देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस, सीमा पार आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन को जल्द अपनाने की भी अपील की गई।

भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्षों और ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका के बीच अंतराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की बात कही गई है। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के आह्वान को दोहराते हुए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत बताई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन के संदर्भ में भी अधिक समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया। घोषणापत्र में कहा गया कि अब



तक कोई महिला संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं बनी है, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से केवल एक तथा अफ्रीका और एशिया से दो-दो नागरिक इस पद पर रह चुके हैं। ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत लगाए जाने वाले एकतरफा दंडात्मक उपायों और आर्थिक तथा द्वितीयक प्रतिबंधों की निंदा की। बयान में कहा गया कि इनका असर आम आबादी के मानवाधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास के अधिकार पर पड़ता है तथा गरीब और कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत सभी एकतरफा दंडात्मक उपायों को समाप्त करने की मांग की। व्यापार के मोर्चे पर नेताओं ने गैर-टैरिफ बाधाओं और भेदभावपूर्ण कार्बन शुल्कों पर

चिंता जताई तथा वैश्विक व्यापार व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और ब्रिक्स भुगतान कार्यबल की प्रगति का स्वागत किया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। नए विकास बैंक के काम की सराहना करते हुए बुनियादी ढांचे और सतत विकास के वित्तपोषण को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए ब्रिक्स ने संवाद, निवारक कूटनीति और मध्यस्थता को महत्वपूर्ण साधन बताया। संबंधित पक्षों की सहमति के आधार पर संघर्षों की रोकथाम और शांति प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। महिलाओं की शांति और सुरक्षा में भागीदारी को लेकर संयुक्त

राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 और उसके बाद के प्रस्तावों को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। शांति और सुरक्षा से जुड़ी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की।

नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा तथा देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता दोहराई गई। वैश्विक व्यापार, आपूर्ति शृंखलाओं और ऊर्जा के सुचारु प्रवाह को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। परमाणु सुरक्षा को लेकर ब्रिक्स ने नागरिक बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा

अगले 5 वर्षों में एसएचजी बहनों को मिलेगा 10 लाख करोड़ का ऋण: शिवराज

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘उद्यम वित्तपोषण और एसएचजी बैंक लिंकेज’ तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत देशभर की लाखों स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्यों, लखपति दीदियों और आवास हितग्राहियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सीधा संवाद किया। चौहान ने बहनों के आर्थिक स्वावलंबन और जीवन स्तर में आए अभूतपूर्व बदलाव की सराहना करते हुए घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में समूहों को 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रु. का व्यक्तिगत ऋण भी शामिल है।

चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन और अवसर पर देशवासियों और सभी बहनों से शाम 7 बजे अपने घरों में कृतज्ञता स्वरूप ‘एक दिया आशीर्वाद का’ जलाने



अंतर्गत पक्का मकान मिलने से उनका जीवन सुरक्षित और गरिमामय हुआ है। लाभार्थियों ने बताया कि आवास के साथ-साथ उज्ज्वला गैस कनेक्शन, नल से जल, शौचालय और आयुष्मान कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं ने उनके परिवारों को नई दिशा दी है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने दीदियों के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि अभाव और मजबूरी का दौर अब समाप्त हो चुका है। ग्रामीण महिलाएं अब न केवल अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि परिवार का आर्थिक संवल बनकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रही हैं।

ब्रिक्स बाजार में दिखी भारत-ईरान की सांस्कृतिक झलक

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में आयोजित ‘ब्रिक्स बाजार’ में भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव की झलक देखने को मिली। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन की बेटी जहरा पेजेशिकयन अपने पति हसन मजीदी के साथ ईरान पवेलियन पहुंचीं।

इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अननपूर्णा देवी ने जहरा पेजेशिकयन का स्वागत किया और उन्हें ब्रिक्स बाजार का भ्रमण कराया। उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों की ओर से प्रदर्शित कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्तुओं और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा। उन्होंने वहां मौजूद कारीगरों और प्रतिनिधियों से बातचीत की तथा उनके द्वारा प्रदर्शित कला और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के क्राफ्ट्स म्यूजियम में आयोजित इस प्रदर्शनी में 18 देशों के 40 से अधिक कारीगर, डिजाइनर और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां अपनी पारंपरिक कला



और हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर रही हैं। यह प्रदर्शनी 15 सितंबर तक चलेगी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई विदेशी मेहमानों और उनके परिवार के सदस्यों के भी इस प्रदर्शनी का दौरा करने की उम्मीद है। ब्रिक्स बाजार

में चीन की सूझोउ कढ़ाई, इंडोनेशिया की पारंपरिक बुनाई, नाइजीरिया की लकड़ी और लौकी से बनी कलाकृतियां तथा दक्षिण अफ्रीका की जुलू चमड़ा कला समेत विभिन्न देशों की प्रामाणिक कला, हस्तशिल्प,



व्यवस्था, संप्रभु समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और मानव गरिमा के सिद्धांतों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। खुशींद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बनाने की बात दोहराई है, उसे लगातार और प्रभावी कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को ईरान पर हुए हमलों को लेकर भारत की कथित स्थिति, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के

दौरान भारत की सीमित कूटनीतिक भूमिका और दक्षिण अफ्रीका पर पड़े कूटनीतिक दबाव के समय पर्याप्त समर्थन नहीं देने जैसे मुद्दों पर विशेष कदम उठाने चाहिए। पार्टी ने कहा कि सरकार को वैश्विक दक्षिण के साझेदारों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए यह प्रदर्शित करना चाहिए कि संकट के समय भी भारत एक विश्वसनीय और रचनात्मक साझेदार है। कांग्रेस ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संबंधों में भारत के लिए अधिक संतुलन की जरूरत बताई। पार्टी के विदेश विभाग की ओर से कहा गया कि ब्रिक्स देशों की वैश्विक वस्तु व्यापार में हिस्सेदारी 19.6 प्रतिशत है, लेकिन ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापारिक संबंध काफी असंतुलित है।

दिल्ली के शेख सराय में 151 करोड़ की लागत से बनेगी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला: रेखा गुप्ता

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली में आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में शेख सराय में अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 151.81 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी गई है। यह जानकारी शनिवार को एक बयान में दी गयी।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को परियोजना का निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है। शेख सराय में बनने वाली नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला लगभग 6,300 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाई जाएगी और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 18,300 वर्गमीटर होगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित यह भवन वैज्ञानिक जांच की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत फोरेंसिक सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से गृह विभाग और दिल्ली पुलिस को नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।



भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कारण आपराधिक मामलों में फोरेंसिक जांच की मांग में

काफी वृद्धि हुई है। नई क्षेत्रीय एफएसएल इस बड़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायता करेगी। इससे आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के लिए

आवश्यक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई आरएफएसएल रोहिणी स्थित मौजूदा एफएसएल की वैज्ञानिक सहायता को मजबूत करेगी। फोरेंसिक विज्ञान आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के साथ-साथ आपराधिक मुकदमों और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नई प्रयोगशाला से राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सहायता को भी मजबूती मिलेगी। इसका विशेष लाभ दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों को मिलेगा।

दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई क्षेत्रीय एफएसएल के शुरू होने के बाद मामलों से जुड़े साक्ष्यों की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम अधिक तेज और सुगम हो जाएगा। नई सुविधा से साक्ष्य आधारित जांच को मजबूती मिलेगी। साथ ही, इससे आपराधिक मामलों को न्यायालयों में समय पर निपटने में सहायता मिलेगी। नई क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से दिल्ली में वैज्ञानिक जांच के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और मध्य दिल्ली के जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ यह सुविधा रोहिणी स्थित एफएसएल को वैज्ञानिक सहायता मजबूत करने में भी सहायक होगी।

ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दिल्ली में ट्रैफिक पर पाबदियां, कई रास्तों पर डायवर्जन

नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। भारत मंडपम और प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ मध्य दिल्ली को दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार डायवर्जन और यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, ये यातायात व्यवस्थाएं सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेंगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी या डायवर्ट की जा सकती है। रिंग रोड, मधुरा रोड, भैरों मार्ग, तिलक मार्ग, इंडिया गेट और सी-हेक्सागन के आसपास यातायात को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सरदार पटेल मार्ग, पटेल रोड,

एनएच-48 और परेड रोड पर भी अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें। खासकर मध्य दिल्ली और नई दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को जहां संभव हो, मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा है कि इससे प्रतिबंधित मार्गों पर संभावित जाम और वीआईपी मूवमेंट के कारण होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन रूट का इस्तेमाल करने और रास्ते में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। आपातकालीन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा।

सिंधु बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-हरियाणा के

बीच स्थित सिंधु बॉर्डर पर दीवारों पर आपत्तिजनक और खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के फरीदकोट से तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख और नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर कथित तौर पर यह वारदात की थी। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रीतपाल, हरमिंदर सिंह और शीशपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, छह सितंबर को सिंधु बॉर्डर की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे और ग्रैफिटी लिखे जाने की सूचना मिली थी। मामले में स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज के आधार पर आरोपितों की आवाजाही का पता लगाया गया और उनकी लोकेशन पंजाब



के फरीदकोट तक पहुंची।

इसके बाद पुलिस टीम ने वहां कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में प्रीतपाल के पन्नू के सीधे संपर्क में होने की बात सामने आई है। आरोप है कि पन्नू के निर्देश पर ही सिंधु बॉर्डर के आसपास दीवारों पर आपत्तिजनक और खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए। जांच एजेंसियां अब प्रीतपाल के

पाकिस्तान में बैठे किसी आतंकी ऑपरेटिव से संभावित संपर्क की भी जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, प्रीतपाल के खिलाफ पहले से ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। तीनों आरोपितों से अलीपुर थाने में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में स्पेशल सेल के साथ इंटील्लिजेंस ब्यूरो की टीमों भी शामिल हैं।

अव्याशी के लिए गन पॉइंट पर 30 लाख की लूट, मास्टरमाइंड समेत चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। अव्याशी और मौजमस्ती के लिए करीब 30 लाख रुपये की लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का कृष्णा नगर थाना पुलिस ने महज आठ घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 19.05 लाख रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल चोरी की स्कूटी, एक देसी पिस्टल और तीन आईफोन 15 प्रो बरामद किए हैं। मामले में फरार आरोपी कैफ की तलाश जारी है।

डीसीपी आरपी मीणा के मुताबिक, 11 सितंबर को विवेक विहार फेज-2 निवासी संजय जैन स्कूटी से करीब 30 लाख रुपये नकद लेकर गांधी नगर की नेहरू गली स्थित रेडीमेड कपड़ों की दुकान की ओर जा रहे थे। नकदी लाल रंग के बैग में रखी थी। इसी दौरान विजय चौक की तरफ से स्कूटी पर आए बदमाशों ने उन्हें पीछे से घेर लिया और गन पॉइंट पर नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो

गए। बदमाशों में से एक के हाथ में चोट लगी थी और उस पर पट्टी बंधी हुई थी। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि सामने आने पर वह आरोपी की पहचान कर सकता है। वारदात की सूचना मिलते ही कृष्णा नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लुटेरों के संभावित भागने के रास्तों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के साथ-साथ पुलिस ने मुखबिरों से मिली जानकारी को भी जांच में शामिल किया। लगातार प्रयास के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और 12 सितंबर को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दीपक को वारदात का मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। दीपक ने पीड़ित के पास बड़ी रकम होने की जानकारी अपने साथियों को दी थी। जांच में कैफ की भी साजिश में भूमिका सामने आई है। हालांकि, वह अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

एमसीडी के टोल नाके बने सिरदर्द, दिल्ली में प्रदूषण और जाम बढने से घट रहा राजस्व, ठेका देने पर उठे सवाल

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। दिल्ली में एमसीडी के टोल नाके एक तरफ प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनसे मिलने वाला राजस्व भी घट गया है। जी हां, टोल से आने वाले राजस्व को अपनी आय का प्रमुख स्रोत बताते वाली एमसीडी का इससे राजस्व घटा है, वहीं इसके वसूलने से होने वाली परेशानी के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बताया गया कि आए दिन प्रमुख टोल नाकों पर व्यावसायिक वाहनों से वसूलने जाने वाले ईसीसी (पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क) और एमसीडी टोल के कारण जाम लगता है। जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यह हालत तब है जब टोल नाकों से जाम खत्म करने के लिए एमसीडी ने 100 करोड़ से अधिक खर्च कर यहां पर रेंडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग आधारित वाहनों का प्रवेश अनिवार्य कर दिया था।



वहीं, बावजूद इसके दिल्ली के नौ टोल नाके (टिकरी बॉर्डर, केजीटी-सिंधु बॉर्डर, कापसहेड़ा बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, अप्सरा-शाहदरा बॉर्डर, न्यू मंडौली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और रजोकारी बॉर्डर) ऐसे हैं जहां पर विशेषकर व्यावसायिक वाहनों से एमसीडी द्वारा टोल वसूली के कारण जाम लगा रहता है। गौरतलब है कि दिल्ली में एमसीडी के 156 टोल नाके हैं, जिनसे एमसीडी को

गए थे, लेकिन एमसीडी की स्थायी समिति का गठन न होने का बहाना लेकर एमसीडी ने इसका एक-एक साल के लिए तीन बार विस्तार किया। अब भी नया ठेका इसी कंपनी को एमसीडी ने दिया है, लेकिन वह भी 950 करोड़ का ही है, जो कि 2017 के मूल ठेके से 250 करोड़ के करीब कम है। एमसीडी ने सहकार ग्लोबल नाम की जिस कंपनी को ठेका दिया है, उस पर सरकारी टोल में वसूली के दौरान राजस्व को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप हैं। एमसीडी की पिछली स्थायी समिति की बैठक में आप पार्षद प्रवीण कुमार ने इस मुद्दे को उठाया था। प्रवीण कुमार ने कहा कि इस कंपनी पर जुलाई 2026 में ही राजस्थान के शाहजहांपुर में एक टोल नाके पर टोल वसूली में राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बावजूद इस कंपनी को हाल ही में फिर से ठेका देना समझ से परे है। दिल्ली की सीमाओं पर जाम और प्रदूषण कम करने के लिए नौ प्रमुख एमसीडी टोल नाकों को हटाने या स्थानांतरित करने की केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्व्यूएम) ने सिफारिश की थी। इनमें टिकरी बॉर्डर, केजीटी-सिंधु बॉर्डर, कापसहेड़ा बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, अप्सरा-शाहदरा बॉर्डर, न्यू मंडौली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और रजोकारी बॉर्डर शामिल थे।

डूसू चुनाव में अभावपि का महिला सुरक्षा और छात्रावास विस्तार पर फोकस

नई दिल्ली, एजेंसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभावपि) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के लिए अपने केंद्रीय पैनल के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य, सचिव पद पर रिखा छाबड़ी एवं संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह अभावपि के प्रत्याशी हैं। चारों पदों पर जीत के लक्ष्य के साथ अभावपि कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों, छात्रावासों एवं विद्यार्थी बहुल क्षेत्रों में लगातार संपर्क और संवाद कर रहे हैं।

अभावपि के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विभिन्न पीजी एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों से संपर्क कर विद्यार्थी हित से जुड़े मुद्दों पर संवाद किया। सत्य निकेतन हादसे के बाद चल रहे ‘आखिर कब तक?’ अभियान के तहत सुरक्षित विद्यार्थी आवास का मुद्दा उठाया गया। अभावपि की मांग और लगातार प्रदर्शनों के बाद 2400 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय



में हॉस्टल की सीमित संख्या और सीटों की कमी को देखते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए

हॉस्टल की सीटें बढ़ाना और सुरक्षित एवं सुलभ आवास उपलब्ध कराना अभावपि का

प्रमुख मुद्दा है। परिषद ने बताया कि महिला सुरक्षा अभावपि का प्रमुख मुद्दा है। पिक बूथ,

सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गश्ती वाहन और यू-स्पेशल बस सेवा जैसी पहलों के साथ ‘नारी तू नारायणी’, ‘स्वयंसिद्धा’ और ‘वामिका’ जैसे अभियानों के माध्यम से छात्राओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा दिया गया है। डूसू में अकादमिक, महिला, पूर्वापार एवं छात्रावास संबंधी समस्याओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ भी बनाए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जा सकें। अभावपि पैनल से डूसू सचिव पद की प्रत्याशी रिखा छाबड़ी ने कहा कि महिला सुरक्षा और हॉस्टल की सुविधा विद्यार्थियों की जरूरतें हैं। अभावपि ने इन मुद्दों को हमेशा जमीन पर उठाया है। अभावपि चाहती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिले और हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के दौरान उचित और सुरक्षित आवास मिल सके। उन्होंने इस बार डूसू में 4-0 से जीत हासिल करने की उम्मीद जताई।

डीटीसी बस सर्विस को हाईटेक करेगाए आई रुट, रस्वरखाव और ड्राइवर-कंडक्टर की इयूटी और पैसेंजर्स पर रखेंगे नजर

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस सेवा, रूट मैनेजमेंट और रखरखाव की निगरानी के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग तकनीक की मदद ली जाएगी।

डीटीसी अपने मौजूदा बस मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर पूरी तरह से एआई आधारित नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की योजना बना रहा है। इसके लिए विशेषज्ञ कंपनियों से प्रस्ताव (आरएफपी) मांगे गए हैं। चयनित कंपनी पहले वर्तमान बस संचालन व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेगी, जिसके बाद इलेक्ट्रिक, सीएनजी व अन्य बसों के प्रबंधन के लिए नया डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा। वर्तमान में डीटीसी के बेड़े में 6,500 से अधिक बसें शामिल हैं, जिनका संचालन शहर के 52 डिपो से किया जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 2028-29 तक बसों की संख्या को बढ़ाकर 14,000 करने और डिपो की संख्या 90 तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। बसों के इस बढ़ते बेड़े को नियंत्रित करने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग बेहद अहम साबित होगी। प्रस्तावित नए एआई सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक



टिकटिंग मशीन (ईटीएम) और किराया वसूली व्यवस्था से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे डिपो, बस, चालक और परिचालक के अनुसार ईटीएम की मैपिंग होगी। मशीनों के जारी होने, लौटने और खराब होने का पूरा हिसाब डिजिटल रहेगा, जिससे राजस्व रिपोर्ट तैयार करने में मैनुअल काम काफी कम हो जाएगा। यह नया सॉफ्टवेयर ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों के अनुसार रियल टाइम में बसों के रूट और शेड्यूल में बदलाव करने में सक्षम होगा। इसके अलावा एआई के इस्तेमाल से बसों के पहुंचने का सटीक समय और देरी की पूरी जानकारी भी मिल जाय करेगी। वहीं, रूट, ड्राइवर-कंडक्टर की इयूटी और इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। ऐसे में बसों में तकनीकी खराबी का पहले से अनुमान, बैट्री क्षमता की निगरानी, सीसीटीवी कवरेज और यात्रियों की संख्या का रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध करने में मदद मिलेगी।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जीएसटी विभाग ने 5 करोड़ का माल जब््त किया



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने रेलवे अधिकारियों के समन्वय से कार्रवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य के कॉपर स्क्रीप समेत लगभग 50 टन माल की खेप जब्त की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कारोबार पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्येक देय कर की वसूली सुनिश्चित हो। रेलवे सहित माल परिवहन के सभी माध्यमों पर निगरानी बढ़ाकर जीएसटी अनुपालन को मजबूत किया जाएगा। सुशासन, पारदर्शिता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में हैं और कर चोरी में शामिल तत्वों के खिलाफ कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बयान के मुताबिक विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि रेलवे नेटवर्क के जरिए अनिवार्य दस्तावेजों, जैसे इनवॉइस और ई-वे बिल के बिना माल का परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। यह खेप आंध्र प्रदेश के रेणिंगुटा से रवाना हुई ट्रेन के जरिए लाई गई थी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 25 टन कॉपर स्क्रीप जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। इसके अलावा करीब 25 टन मिश्रित स्क्रीप, कपड़े और अन्य सामान भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। इस प्रकार पकड़े गए माल का कुल अनुमानित मूल्य करीब 5 करोड़ रुपये है। पकड़े गए माल के साथ आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा अब माल की जांच संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही, जीएसटी कानून के तहत माल के परिवहन से संबंधित वैधानिक अनुपालन की भी जांच की जा रही है। विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई सड़क मार्ग के अलावा रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले माल के परिवहन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय और रेलवे मार्गों की निगरानी बढ़ाकर बिना हिसाब-किताब के माल, अनियमित दस्तावेजों और संभावित कर चोरी के मामलों का पता लगाने के प्रयास तेज किए जा रहें हैं।

पत्नी की हत्या में पति और प्रेमिका गिरफ्तार, शादी की चाहत में रची थी साजिश

नई दिल्ली। शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र के प्रह्लादपुर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति और उसकी कथित प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पति ने प्रेमिका से शादी करने की चाहत में अपनी पत्नी सबीला खातून की हत्या की साजिश रची थी। वारदात के बाद दोनों दिल्ली से फरार हो गए थे। पुलिस ने दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मुंबई में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों का सुराग लगाया। पुलिस ने मामले में मृतका के पति मोहम्मद लाल बाबू उर्फ जाहिद अली और उसकी कथित प्रेमिका रूखसार खातून को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस लाल बाबू के ममेरे भाई मोहम्मद उसामा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उसामा पर आरोप है कि उसने हत्या के बाद लाल बाबू को पनाह दी और उसे बिहार पहुंचने में मदद दी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। सबीला खातून अपने पति लाल बाबू के साथ प्रह्लादपुर स्थित मकान नंबर 416 में रहती थी। 129 आरोपितों में हत्या की हत्या के संबंध में शाहबाद डेयरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लाल बाबू के रुखसार खातून से कथित तौर पर संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था। इसी वजह से दोनों ने सबीला को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि साजिश के तहत सबीला की घर के बाथरूम में हत्या की गई। वारदात के बाद लाल बाबू अपने नाबालिग बेटे को साथ लेकर दिल्ली से फरार हो गया। वह पहले नोएडा पहुंचा और वहां अपने ममेरे भाई उसामा से संपर्क किया। आरोप है कि उसामा ने उसे पनाह दी और पुलिस से बचने के लिए बिहार जाने में मदद की। वारदात के बाद आरोपितों के दिल्ली से बाहर भाग जाने के कारण पुलिस के सामने उनकी तलाश चुनौती बन गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहबाद डेयरी थाना और बाहरी उत्तर जिला स्पेशल स्टॉफ की कई टीमों गठित की गईं। टीमों ने तकनीकी जांच के साथ स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई और आरोपितों के संभावित ठिकानों की पहचान की।

एक नजर

फरीदाबाद में डेंगू, मलेरिया व स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा

फरीदाबाद। फरीदाबाद में बदलते मौसम और बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 13, मलेरिया के तीन और स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आए हैं। एक साथ कई बीमारियों के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच तेज कर दी है। करीब 40 टीमों अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर मच्छरों के लार्वा की जांच और सैंपलिंग कर रही हैं। टीमों की ओर से घरों और आसपास के इलाकों में पानी जमा होने वाले स्थानों की भी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, खाली बर्तनों और अन्य जगहों पर जमा पानी की जांच कर रही हैं। इन जगहों पर पानी जमा रहने से डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पनप सकता है। लोगों को भी अपने घरों और आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जांच के दौरान जहां भी मच्छरों का लार्वा मिल रहा है, वहां लोगों को पानी जमा न होने देने की हिदायत दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि मच्छरों की रोकथाम के लिए लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1,660 लोगों को नोटिस जारी किए हैं सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने कहा कि विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है। डेंगू और मलेरिया के साथ स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर भी निगरानी कर रहा है। स्वाइन फ्लू में तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी गई है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और रात में मच्छरदानी या अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

नकली एशियन पेंट्स बेचते हुए दुकान मालिक पकड़ा

फरीदाबाद। एसजीएम नगर इलाके में नकली एशियन पेंट्स बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुकान पर शनिवार को छापेमारी कर नकली पेंट से भरी छह बाल्टियां बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने दुकान मालिक विकास गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार एशियन पेंट्स कंपनी के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से जुड़े मामलों की जांच करने वाली टीम को सूचना मिली थी कि एसजीएम नगर क्षेत्र की एक दुकान पर कंपनी के नाम से नकली पेंट बेचा जा रहा है। इसके बाद कंपनी की ओर से जांच अधिकारी अनुज कुमार ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम अनुज कुमार के साथ गुप्ता पेंट और हार्डवेयर दुकान नंबर डी- 121, पटेल चौक के पास पहुंची। यहां दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने अपमान नाम विकास गुप्ता बताया और खुद को दुकान का मालिक बताया। तलाशी लेने पर दुकान से एशियन पेंट्स के नाम वाली छह बाल्टियां बरामद हुईं। पुलिस के मुताबिक बरामद बाल्टियों में एपेक्स डस्ट प्रूफ की 20 और 10 लीटर की बाल्टियां, एपेक्स शाइन 20 लीटर,एपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन 20 लीटर और ट्रैक्टर इमल्शन की 20 और 10 लीटर की बाल्टियां शामिल हैं। इन सभी में अलग-अलग तरह का पेंट भरा हुआ था। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में ले लिया। एसजीएम नगर थाना प्रभारी अरविन्द ने बताया कि विकास गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

112 साल बाद मिला पहले विश्व युद्ध के शहीद का रिकॉर्ड

गुरुग्राम। इतिहास में गुम हो चुके वीरों को सम्मान दिलाने के लिए हरियाणा में एक बड़ी मुहिम को लगातार गति मिल रही है। इस संबंध में एक शोधकर्ता ने पटौदी खंड के पथरेड़ी गांव के दो गुप्तनाम नायकों के ऐतिहासिक दस्तावेज खोजे हैं। शोधकर्ता भगवान फौगाट (स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह के पुत्र) और शहीद स्वतंत्रता सेनानी गेराम लोहचब के पड़पोते हैं। उन्होंने नेशनल आर्काइव्स और अंतरराष्ट्रीय सैन्य रिकॉर्ड खंगाल कर यह प्रमाण जुटाए हैं। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के रिकॉर्ड के अनुसार, पथरेड़ी निवासी सिपाही चेत राम पुत्र परम सुख ने प्रथम विश्व युद्ध में चार अप्रैल 1914 को बलिदान दिया था। 112 साल बाद शहीद चेत राम का बलिदान सामने आया है। उनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिमेंबरेंस में दर्ज है, लेकिन अब तक गांव के गौरव-पट्ट पर उनका नाम नहीं है। इसी तरह से जुग लाल नामक स्वतंत्रता सेनानी की भी गुप्तनामी से बाहर निकाला गया है। हूज हू स्वतंत्रता सेनानी संकलन के अनुसार, जुग लाल पुत्र टेक राम का जन्म 1907 में पथरेड़ी में हुआ था। वे पहले 4/19 हैदराबादी रेजिमेंट में थे। फिर 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड में शामिल होकर देश के लिए लड़े, बंदी बने और यातनाएं झेलीं। शोधकर्ता ने प्रशासन और पंचायत से मांग की है कि दोनों वीरों के नाम राजकीय सम्मान के साथ पथरेड़ी के गौरव-पट्ट पर अंकित किए जाएं। शोधकर्ता भगवान फौगाट ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि वे अपने गांवों के गौरव-पट्ट की फोटो सझा करें। अगर किसी वीर का नाम छूटा है तो वे आर्काइव्स से प्रमाण खोजकर उन्हें सम्मान दिलाने में मदद करेंगे।

पर हर विधानसभा में जलाए जाएंगे 30 हजार आशीर्वाद के दीये: डॉ. अर्चना गुप्ता

गुरुग्राम,एजेंसी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन, त्याग, बलिदान और बेदाग जीवन के 25 साल के सेवा संकल्प अभियान को प्रदेश सरकार और भाजपा आमजन के साथ समन्वय करते हुए सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर प्रत्येक हरियाणवीं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से प्रारंभ अभियान को सेवा दिवस के तौर पर मनाते हुए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 30 हजार आशीर्वाद के दीये जलाने से आगाज होगा, जो एक दर्जन कार्यक्रमों की श्रृंखला के तौर पर 17 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा संकल्प अभियान भाजपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के हर वर्ग और प्रत्येक हरियाणवीं की भागीदारी से इसे जनाभियान बनाया जाएगा। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि विभिन्न संगठनों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वयं इस अभियान से जुड़े कार्यक्रम करने को लेकर उनसे संवाद



किया गया है, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आमजन में कितना विश्वास है। उन्होंने कहा कि, एक ओर जहां आमजन, विभिन्न योजना के लाभार्थी अपने घर पर दीया जलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर एक लाख दीये, पानीपत के देवी मंदिर में 50 हजार दीये के साथ-साथ गुरुग्राम में प्राचीन माता शीतला माता मंदिर पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर,

गुरुग्राम: चर्चाओं का वास्तविक महत्व धरातल पर कर्म के रूप में दिखाई देना: प्रो. वी.के. पॉल

गुरुग्राम। बोहड़ा कलां स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शनिवार को साईंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ। डिस्कवर, डिजाइन एंड ट्रांसफॉर्म विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देशभर से आए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और वास्तुकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक मूल्यों के मेल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के निदेशक प्रो. वी.के. पॉल ने कहा कि अकादमिक या वीचारिक चर्चाओं का वास्तविक महत्व तभी है जब वे धरातल पर कर्म के रूप में दिखाई दें। उन्होंने जोर दिया कि जिम्मेदारियों को ठोस परिणाम में बदलना ही आध्यात्मिकता का असली मकसद है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व महानिदेशक हरि बाबू श्रीवास्तव ने अहंकार को प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा केवल सच्चे

ज्ञान से मिलती है। संस्थान के साईंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजयोगी बीके मोहन सिंघल ने कहा कि राजयोग के नियमित अभ्यास से न केवल जीवन संवरता है, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता से निभाने और बेहतर प्रबंधन (मैनेजमेंट) की कला भी सिखाता है।

ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता जीवन में विनम्रता और शांति का संचार करती है। विज्ञान के बड़े से बड़े आविष्कार भी मौन की गहराइयों से जन्म लेते हैं। साईंस और साइलेंस एक-दूसरे के पूरक हैं। जब हमारे विचार श्रेष्ठ और सकारात्मक होंगे, तभी एक सुंदर और नई दुनिया का निर्माण संभव हो सकेगा। राजयोग का निरंतर अभ्यास मन और बुद्धि पर नियंत्रण सिखाता है। जब मन शुद्ध होता है, तो उससे जन्महतकारी और नए आविष्कार जन्म लेते हैं। प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजयोगी बीके भारत भूषण ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं के बीच अवसर तलाशने का धैर्य देती है।

ग्रेटर नोएडा में सितंबर में ही छाने लगी दिसंबर जैसी धुंध, साइट-बी की चिमनियां से निकल रहा काला धुआं



ग्रेटर नोएडा। अभी सितंबर का करीब आधा वाह ही बीता है। नवंबर और दिसंबर आना अभी बाकी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में दिसंबर जैसी धुंध छाने लगी है। शहर के औद्योगिक क्षेत्र साइट-बी स्थित फैक्ट्रियों की चिमनियां दिन-रात काला धुआं उगल रही हैं। आरोप है कि इन ऊंची चिमनियों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और प्लूट गैस डिस्लफराइजेशन स्क्रबर लगाए जाते हैं।

इससे प्रदूषण कण काफी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं हवा में नहीं घुल पाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस पर अमल नहीं करा पा रहा है। इससे केमिकल और धुएं के गुबार से पूरा इलाका प्रदूषित हो रहा है,

लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्राधिकरण आंख मूंदे बैठे हैं। कामगारों का कहना है कि सुबह-शाम साइट-बी की सड़कों पर धुंध जैसी स्थिति रहती है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कई इकाइयों में बिना फिल्टर के चिमनियां चल रही हैं। केमिकल की दुर्गंध से आंखों में जलन और सांस की दिक्कत आम हो गई है। कामगारों को मजबूरी में इसी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्त रूप से टायर, प्लास्टिक, केमिकल और पेंट की कई इकाइयां हैं। नियमों के अनुसार चिमनियों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना अनिवार्य है, लेकिन कई फैक्ट्रियों में मानकों का पालन नहीं हो रहा। शाम ढलते ही कई फैक्ट्रियां चोरी-छिपे कचरा और केमिकल वेस्ट भी जलाती हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है।

हड़ताल खत्म, 36 दिन बाद काम पर लौटे सफाई कर्मचारी



फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद में 36 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार सरकार के साथ मांगों पर सहमति बनने के बाद खत्म हो गई। हड़ताल समाप्त होते ही शनिवार सुबह नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में काम पर लौट आए। लंबे समय से कहां, कहां लंबे समय से कूड़ा जमा है। कर्मचारियों ने सबसे पहले बाजारों, मुख्य सड़कों और कॉलोनियों की गलियों में सफाई शुरू की। नगर निगम सफाई कर्मचारी नेता बलबीर

सबसे पहले बाजारों, मुख्य सड़कों और कॉलोनियों की गलियों में सफाई शुरू की। कई स्थानों पर घरों और दुकानों के बाहर जमा कूड़े के ढेर उठाए गए। इसके अलावा नालियों में जमा गंदगी और कचरे को भी हटाया गया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि प्राथमिकता उन इलाकों को दी जा रही है, जहां लंबे समय से कूड़ा जमा है। कर्मचारियों ने सबसे पहले बाजारों, मुख्य सड़कों और कॉलोनियों की गलियों में सफाई शुरू की। नगर निगम सफाई कर्मचारी नेता बलबीर

जौंद में रानी तालाब समेत कई स्थानों पर आयोजन प्रस्तावित हैं। 17 सितंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में रक्तदान शिविर का आगाज होगा, जो प्रतिदिन एक जिला में बड़े रक्तदान शिविर के तौर पर आयोजित किया जाएगा, इनमें रक्तदाता, विशेषकर युवा वर्ग बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी करेगा। अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच और मोतियाबिंद उपचार शिविर लगाए जाएंगे।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चों को वीरों की कहानियों से जोड़ा जाएगा, ताकि उनमें राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना मजबूत हो। इस अवसर पर स्वामी धर्मदेव एवं पूर्व कुलपति डॉ. अशोक दिवाकर द्वारा भी आमजन से सेवा संकल्प अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता, प्रदेश महामंत्री वेद फुल्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी आदि उपस्थित रहे।

ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से यूपीआईटीएस, रूस-जापान समेत कई देशों के निवेशकों से जुड़ेंगे यूपी के कारोबारी

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

ग्रेटर नोएडा। नालेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंडमार्ट में 25 सितंबर से आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण का शुभारंभ हो रहा है। इसका आयोजन 29 सितंबर तक होगा। यह वैश्विक व्यापार और उत्तर प्रदेश की विनिर्माण क्षमता को एक मंच पर लाने वाला प्रमुख आयोजन होगा। इसमें रूस की भागीदारी भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। ब्रिक्स में भारत के साथ रूस की महत्वपूर्ण भूमिका के बीच यूपीआईटीएस-2026 में बीटूबी राउंडटेबल और सरकारी स्तर की बातचीत के माध्यम से दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा। यूपीआईटीएस में रूसी उद्योगों और उत्तर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र के बीच सीधे संवाद से नए व्यापारिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क मजबूत होने के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग व वैकल्पिक वैश्विक व्यापार मार्गों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आस्ट्रिया की भागीदारी के तहत भारत के मुक्त व्यापार समझौतों



का वैश्विक कारोबारी विकास के लिए उपयोग जैसे विषयों पर ज्ञान सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इसका उद्देश्य स्थानीय निर्माताओं, कारीगरों और व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने तथा नीतिगत अवसरों को व्यावहारिक निर्यात क्षमता में बदलने पर केंद्रित होगा। जापान की भागीदारी में जेट्रो से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे 500 एकड़ के जापानी औद्योगिक शहर का विकास भारत-जापान औद्योगिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जापान के साथ लंबे समय से चले आ रहे विश्वास और औद्योगिक सहयोग से उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, हार्ड-टेक विनिर्माण और निवेश क्षमता को मजबूती मिल रही

डेंगू से बचाव आसान है

आपकी सतर्कता आपको और परिवार को डेंगू से बचा सकती है



डेंगू का मच्छर साफ रूके हुए पानी में पैदा होता है

मच्छर पैदा न होने दें

मच्छर के काटने से बचें



गमले, फूलदान या घर के आस-पास कहीं भी पानी जमा न होने दें।



कूलर के पानी को हर सप्ताह खाली करें या उसमें थोड़ा पेट्रोल/तेल डाल दें।



पानी की टंकी, बाल्टी व अन्य बर्तनों को पूरी तरह ढक कर रखें।



अनुपयोगी कबाड़ जैसे कि टूटे बर्तन, बोतल, टिन, टायर और नारियल के खोल इत्यादि को खुले में न रखें/फेंके।



पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें एवं मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।



बुखार के समय घर व अस्पताल में मच्छरदानी का नियमित इस्तेमाल करें।

डेंगू के लक्षण



तेज बुखार



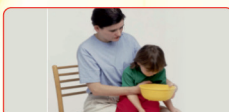
आंखों के पीछे तेज दर्द, जो आंखों के घुमाने से बढ़ता हो



सर दर्द, मासपेशियों एवं जोड़ों में दर्द



पेट दर्द



जी चिचलाना, उल्टी आना



शरीर पर दाने निकलना

उपरोक्त लक्षण दिखाई देने पर इलाज के लिए अपने निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें			
डेंगू की जांच व उपचार सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है			
For Any Queries, Please Contact : Name of DHOs with Contact Number & Zone (District)			
1. Dr. Hemant Kumar City SP (Old Delhi)	9990978034	5. Dr. V.N. Bhagat KPZ (Central North)	9717750141
2. Dr. Nageshwar Marandi Central (South East)	9958001160	6. Dr. Madhura Panth Narela (Outer North)	9958648615
3. Dr. Sandeep Salve Civil Line (North)	8600598179	7. Dr. Vishal C. Soyam Najafgarh (South West)	9560945471
4. Dr. Aniket Sirohi KBZ (Central)	7217785459	8. Dr. Kanika Singh Rohini (North West)	9319733556
9. Dr. Ajay Handa Shahdra-s (East)	9811015714	10. Dr. Santosh Tomar Shahdra-s (North East)	9818579090
11. Dr. Deepak Mittal South (South)	8130698279	12. Dr. Ajay Kumar West (West)	9871663908

सौजन्य से : जन स्वास्थ्य विभाग दिल्ली नगर निगम द्वारा जम्माई से जारी



राष्ट्रीय वेक्टर जमित रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, दिल्ली सरकार



एआई से 1980 की फोटो बना रहे हैं तो हो जाएं सावधान!

अमरेश द्विवेदी

आजकल सोशल मीडिया पर 1980 के दशक जैसी विंटेज फोटो बनाने का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग अपनी सामान्य तस्वीरों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से पुरानी फिल्मों, कैमरा क्वालिटी और उस दौर के फैशन के अंदाज में बदलकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। कुछ सेकंड में तैयार होने वाली ये तस्वीरें देखने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन इनके पीछे मौजूद डेटा प्राइवेंसी और साइबर सिक्योरिटी के जोखिमों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जरा सोचिए, आपने अपने मोबाइल से अपनी एक सामान्य फोटो चुनी और उसे किसी एआई ऐप या वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही सेकंड में आपकी तस्वीर 1980 के दशक की पुरानी और विंटेज फोटो में बदल जाती है। तस्वीर पसंद आती है और आप उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद लाइक और कमेंट का इंतजार शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस फोटो को आपने कुछ सेकंड पहले किसी एआई ऐप या वेबसाइट पर अपलोड किया था, वह अब कहाँ है? क्या वह तस्वीर केवल आपके मोबाइल में वापस आई है या उस सर्वर पर भी स्टोर हुई है? क्या ऐप उसे कुछ समय बाद डिलीट करता है या लंबे समय तक अपने सिस्टम में रख सकता है? क्या उस फोटो का इस्तेमाल सेवा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है?

और सबसे अहम सवाल— आपकी फोटो के साथ आपकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है? आज के डिजिटल दौर में चेहरे की तस्वीर केवल एक तस्वीर नहीं रह गई है। यह आपकी डिजिटल पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक लगातार विकसित हो रही है और कई ऑनलाइन सेवाएं फोटो और अन्य व्यक्तिगत डेटा के साथ काम करती हैं। यही वजह है कि किसी अनजान एआई ऐप या वेबसाइट पर अपनी फोटो अपलोड करने से पहले उसकी प्राइवेंसी पॉलिसी और डेटा इस्तेमाल करने की शर्तों को समझना जरूरी है। अगर किसी सेवा की शर्तों में यह स्पष्ट नहीं है कि अपलोड की गई तस्वीर कितने समय तक रखी जाएगी, उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होगा या उसे किन पक्षों के साथ साझा किया जा सकता है, तो सावधानी बरतना बेहतर है। एआई तकनीक ने तस्वीरों और वीडियो को बदलना बेहद आसान बना दिया है। इसी तकनीक का



गलत इस्तेमाल करके डीपफेक भी बनाए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के चेहरे को दूसरी तस्वीर या वीडियो में लगाकर ऐसी सामग्री तैयार की जा सकती है, जो देखने में वास्तविक लग सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एआई ऐप पर फोटो अपलोड करते ही आपकी तस्वीर डीपफेक बन जाएगी। लेकिन इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आपकी तस्वीरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उनका गलत इस्तेमाल किए जाने का जोखिम भी बढ़ सकता है। खासकर ऐसी तस्वीरों को लेकर ज्यादा सावधानी जरूरी है जिनमें चेहरा साफ दिखाई देता हो। साइबर सुरक्षा का खतरा केवल फोटो अपलोड करने तक सीमित नहीं है। कई बार लोग सोशल मीडिया

पर वायरल हो रहे किसी ट्रेंड के पीछे भागते हुए अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं और फिर किसी ऐप को जरूरत से ज्यादा परमिशन दे देते हैं। अगर कोई ऐप फोटो एडिट करने के नाम पर कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स या अन्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मांग रहा है, तो एक बार जरूर सोचें कि उसे वास्तव में उस परमिशन की जरूरत क्यों है। हर परमिशन खतरनाक नहीं होती। उदाहरण के लिए, फोटो एडिटिंग ऐप को किसी तस्वीर तक पहुंच की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर किसी साधारण ऐप की मांग उसकी वास्तविक जरूरत से मेल नहीं खाती, तो परमिशन देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। साइबर अपराधी अक्सर वायरल ट्रेंड का फायदा

उठाते हैं। किसी लोकप्रिय एआई फोटो ट्रेंड के नाम पर फर्जी वेबसाइट या ऐप तैयार किया जा सकता है और लोगों को वहां अपनी तस्वीर या व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। कुछ मामलों में फर्जी वेबसाइटें यूजर से इंस्टाग्राम, फेसबुकया ईमेल का पासवर्ड डालने के लिए भी कह सकती हैं। यह बेहद खतरनाक हो सकता है। किसी एआई फोटो टूल को इस्तेमाल करने के लिए अगर आपसे सोशल मीडिया का पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो तुरंत रुकें और वेबसाइट की विश्वसनीयता की जांच करें। अनजान लिंक पर लॉगिन जानकारी दर्ज करना साइबर अपराधियों को आपका अकाउंट सौंपने जैसा हो सकता है। 1980 के

ब्रिक्स का सबसे बड़ा महत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में है। भारत लंबे समय से ऐसी विदेश नीति का समर्थन करता रहा है जिसमें किसी एक शक्ति-गुट पर निर्भरता के बजाय विभिन्न देशों और मंचों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध बनाए जाए। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत की भागीदारी है, वहीं भारत अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य शक्तियों के साथ भी समानांतर रूप से सहयोग करता है। इस प्रकार ब्रिक्स भारत की बहु-संरेखीय विदेश नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। ब्रिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देना है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आज भी अनेक निर्णय ऐसी संरचनाओं के भीतर लिए जाते हैं, जिनमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व उनकी आर्थिक और जनसंख्या संबंधी भूमिका के अनुरूप नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता लगातार उठाता रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देश सामूहिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तृत सदस्यता का अर्थ है बड़े बाजारों, निवेश, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग की नई संभावनाएं।

ब्रिक्स: भारत की नई हुंकार

डॉ. सत्यवान सौरभ

ब्रिक्स आज केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक समूह नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रभावी बनाने वाला महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन से बने 'ब्रिक' में 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्ण सदस्य बने तथा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस विस्तार के साथ ब्रिक्स अब 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत के लिए वर्ष 2026 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत ने एक जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की अध्यक्षता का केंद्रीय दृष्टिकोण लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। यह अध्यक्षता भारत को केवल आयोजक की भूमिका नहीं देती, बल्कि समूह की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को प्रभावित करने का अवसर भी प्रदान करती है।

ब्रिक्स का सबसे बड़ा महत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में है। भारत लंबे समय से ऐसी विदेश नीति का समर्थन करता रहा है जिसमें किसी एक शक्ति-गुट पर निर्भरता के बजाय विभिन्न देशों और मंचों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध बनाए जाएं। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत की भागीदारी है, वहीं भारत अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य शक्तियों के साथ भी समानांतर रूप से सहयोग करता है। इस प्रकार ब्रिक्स भारत की बहु-संरेखीय विदेश नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। ब्रिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देना है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आज भी अनेक निर्णय ऐसी संरचनाओं के भीतर लिए जाते हैं, जिनमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व उनकी आर्थिक और जनसंख्या संबंधी भूमिका के अनुरूप नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता लगातार उठाता रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देश सामूहिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद, व्यापारिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ब्रिक्स के भीतर व्यापारिक बाधाओं को कम करने और भुगतान प्रणालियों को अधिक सुविधाजनक बनाने पर सहयोग भारत के आर्थिक हितों को लाभ पहुंचा सकता है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग की संभावनाएँ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। ब्रिक्स वित्त के क्षेत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। विकासशील देशों के लिए ऐसी संस्थाएँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पारंपरिक वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के विकल्प और पूरक दोनों



के रूप में काम कर सकती हैं। भारत के लिए इसमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास, जलवायु और हरित बुनियादी ढाँचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं, लेकिन ब्रिक्स के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसके सदस्य देशों के विविध और कई बार परस्पर विरोधी रणनीतिक हित हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा किसी भी गहरे राजनीतिक या सुरक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकती है। रूस-पश्चिम संघर्ष, पश्चिम एशिया की परिस्थितियाँ और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता जैसे वैश्विक घटनाक्रम भी ब्रिक्स के भीतर मतभेद पैदा कर सकते हैं।

दूसरी चुनौती है विस्तार के बाद समन्वय की जटिलता। जब समूह छोटा था, तब साझा दृष्टिकोण बनाना अपेक्षाकृत आसान था। अब 11 पूर्ण सदस्यों और अलग-अलग स्तर के साझेदार देशों के साथ निर्णय-निर्माण अधिक जटिल हो गया है। प्रत्येक देश की आर्थिक संरचना, राजनीतिक प्राथमिकताएं और विदेश नीति अलग हैं। इसलिए केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं; साझा एजेंडा और प्रभावी संस्थागत तंत्र भी आवश्यक हैं। एक और गंभीर चुनौती यह है कि ब्रिक्स को कहीं पश्चिम-विरोधी गठबंधन के रूप में देखने की प्रवृत्ति न बढ़ जाए। यदि समूह को केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों के विकल्प या प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उसके विकासात्मक और आर्थिक उद्देश्यों को नुकसान पहुंच सकता है।

भारत के हित में यही होगा कि ब्रिक्स को किसी के विरुद्ध खड़े गुट के बजाय बहुध्रुवीय और समावेशी सहयोग मंच के रूप में

विकसित किया जाए। भारत की 2026 की अध्यक्षता इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत को घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक परिणामों पर जोर देना चाहिए। व्यापार और निवेश, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की कार्यक्षमता और परियोजना-वित्त क्षमता को मजबूत करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। अंततः ब्रिक्स की सफलता इस बात से तय होगी कि वह वैश्विक राजनीति में कितने प्रभावशाली बयान जारी करता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह कितना व्यावहारिक सहयोग पैदा करता है। भारत के लिए ब्रिक्स रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक अवसर, वैश्विक दक्षिण की सामूहिक शक्ति और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मंच है। इसकी विविधता चुनौती अवश्य है, लेकिन वही इसकी शक्ति भी बन सकती है। भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान सहमति, संवाद और विकास को केंद्र में रखकर ब्रिक्स को ऐसा मंच बनाना चाहिए, जो किसी शक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समानता, सहयोग और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में खड़ा हो। ब्रिक्स भारत के लिए केवल कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका को आकार देने का अवसर है। यदि भारत अपनी अध्यक्षता को व्यावहारिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की एकजुटता और संतुलित कूटनीति से जोड़ने में सफल होता है, तो ब्रिक्स की नई दिशा में उसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है।

विचार

करेंसी को टिकाऊ बनाने की दिशा में अहम बदलाव

पुष्परंजन

भारत की मुद्रा केवल कागज, सुरक्षा धागे और स्याही का भौतिक उत्पाद नहीं है; यह देश की संप्रभुता का प्रतीक, रोज़मर्रा के सामाजिक भरोसे का ठोस माध्यम और राज्य की संस्थागत क्षमता का प्रतीक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छोटे मूल्यवर्ग,खासकर 10 रुपये और 20 रुपये, में पॉलिमर यानी प्लास्टिक नोटों के बड़े पैमाने पर फील्ड ट्रायल की दिशा में उड़ाए गए हालिया नीतिगत कदम देश की मौद्रिक यात्रा में दूरगामी मोड़ हैं। यह पहल नोटों के टिकाऊपन, मुद्रण लागत में कटौती व जालसाजी पर अंकुश का वादा तो करती है, लेकिन साथ ही पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समावेशिता और करेंसी सुधार की राजनीति पर भी गंभीर विमर्श की मांग करती है। वैश्विक पटल पर पॉलिमर बैंकनोट्स कोई सर्वथा नया प्रयोग नहीं हैं। वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर ब्रिटेन, कनाडा, वियतनाम और नाइजीरिया जैसे देशों ने इसे सफलतापूर्वक अपनाया है। इन देशों में पॉलिमर करेंसी को अपनाने का मुख्य कारण उसका लंबा जीवनकाल और उन्नत सुरक्षा तंत्र रहा है। पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में पॉलिमर नोट औसतन तीन से चार गुना अधिक चलते हैं। भारत में छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की स्थिति जमीनी स्तर पर अत्यंत दयनीय रहती है। सब्जी मंडी, ऑटो-रिक्शा, चाय की थड्डियों और स्थानीय हाट-बाज़ारों में 10 और 20 रुपए के नोट इतनी तेजी से हाथ बदलते हैं कि उनका औसत जीवनकाल बमुरिक्ल एक वर्ष ही रह जाता है। पसीने, नमी, धूल और बार-बार मोड़ने-मरोड़ने के कारण वे जल्द ही फट जाते हैं। रिज़र्व बैंक की 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत प्रतिवर्ष अरबों की संख्या में कटे-फटे और मैले नोट नष्ट कर उनकी जगह नोट छापने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में भारी वित्तीय संसाधन, विदेशी सबस्ट्रेट यानी नोट-पेपर का आयात और लॉजिस्टिक्स का खर्च शामिल होता है। पॉलिमर नोट पानी, तेल और गंदगी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इन्हें बार-बार बदलने की दर घटने से केंद्रीय बैंक के मुद्रण खर्च में बड़ी कमी आएगी। इसके साथ ही, पारदर्शी 'विंडो' और जटिल ऑप्टिकल सुरक्षा विशेषताओं के चलते नकली नोटों के संगठित नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना कहीं अधिक संभव हो सकेगा। पॉलिमर नोटों का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की विशाल अनौपचारिक इकोनॉमी पर पड़ेगा। रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और ग्रामीण परिवार रोज़मर्रा के लेन-देन के लिए मुख्य रूप से नकदी पर ही निर्भर हैं। जब किसी आम नागरिक के हाथ में फटा हुआ नोट आता है और बाज़ार में उसे लेने से मना कर दिया जाता है, तो यह सिर्फ आर्थिक हानि नहीं बल्कि रोज़मर्रा की असुविधा और गरिमा पर चोट का कारण बनता है। लंबे समय साफ़-साबुत रहने वाले नोट आम जनता को लेन-देन में सुगमता और मानसिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह नीतिगत क़दम इस व्यावहारिक सच्चाई को भी स्वीकार करता है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अभूतपूर्व प्रसार के बावजूद भारत में नकद लेन-देन पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। डिजिटल भुगतान की बुनियादी सीमाएं हैं—नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता की बाधाएं अभी पूरी तरह दूर नहीं हुईं। प्रस्तावित पॉलिमर नोट कागजी मुद्रा के समांतर चलेंगे, जिससे सुनिश्चित होगा कि तकनीकी रूप से वंचित वर्ग वित्तीय प्रणाली के हाशिए पर न हों।

हालाँकि, पॉलिमर नोटों की चमक के पीछे दो प्रमुख चुनौतियां भी छिपी हैं—पहली पर्यावरणीय और दूसरी सांस्कृतिक व जलवायुगत। पॉलिमर नोट प्लास्टिक आधारित होने के कारण गैर-बायोडिग्रेडेबल हैं। भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग का ढांचा अभी भी पूरी तरह संगठित नहीं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने पुराने पॉलिमर नोटों को रिसाइक्ल कर उनसे उपयोगी औद्योगिक उत्पाद बनाने की व्यवस्था तैयार की है। यदि भारत समय रहते मुद्रण के साथ-साथ ऐसे नोटों के वैज्ञानिक संकलन और रिसाइक्लिंग का तंत्र विकसित नहीं करता, तो वित्तीय बचत से अधिक बड़ा नुकसान पर्यावरणीय लागत के रूप में सामने आ सकता है। दूसरी चुनौती भारत की विविध और चरम जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी है। भीषण गर्मी, अत्यधिक नमी और धूल भरे माहौल में पॉलिमर नोटों के व्यवहार का जमीनी आकलन अनिवार्य है। इसके साथ ही, भारतीय संदर्भ में नोटों के सबस्ट्रेट को सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनाओं के अनुकूल रखना भी आवश्यक शर्त रही है। आम बोलचाल में 'प्लास्टिक' शब्द कई बार कुमिमात और अविश्वास से जुड़ जाता है; ऐसे में जनमानस में इन नोटों की प्रामाणिकता और वैधता स्थापित करने के लिए जन-जागरूकता जरूरी होगी। पॉलिमर नोट महज एक तकनीकी या प्रशासनिक सुधार नहीं; वे पारंपरिक कागजी मुद्रा और भविष्य की पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच एक 'संक्रमणकालीन सेतु' की तरह हैं।

एक नजर

जनता दरबार में दर्जनों भू-विवाद मामलों का निष्पादन, प्रशासनिक सक्रियता से जमी नई उम्मीद



दरभंगा,एजेंसी। दरभंगा जिला अंतर्गत तारहीड प्रखंड में नवपदस्थापित अंचलाधिकारी आलोक कुमार एवं सकतपुर थानाध्यक्ष अरविंदर कुमार के नेतृत्व में शनिवार को आयोजित नियमित जनता दरबार में विभिन्न पंचायतों से पहुंचे भू-विवाद से संबंधित दर्जनों मामलों की सुनवाई कर उनके निष्पादन की कार्रवाई की गई। जनता दरबार में अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत समाधान की दिशा में पहल की। अंचलाधिकारी आलोक कुमार के कार्यशैली की खासियत उनकी सक्रियता और कार्यालय में पर्याप्त समय देकर लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर देना बताया जा रहा है। वे अपने सहकर्मियों के साथ लंबित फाइलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक आदेश पारित करने तथा मामलों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उनकी कार्यशैली में त्वरित निर्णय के साथ नियम–कानून का पालन प्रमुखता से दिखाई देता है। वहीं, सकतपुर थानाध्यक्ष अरविंदर कुमार भी क्षेत्र में कानून–व्यवस्था से जुड़े मामलों पर बारीकी से नजर रखते हुए शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई के लिए जाने जा रहे हैं। भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सक्रियता और पुलिस की तत्परता से लोगों में यह उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के समाधान तथा कानून–व्यवस्था से जुड़े मामलों में तेजी आएगी। अंचल प्रशासन और सकतपुर थाना की समन्वित कार्यशैली से तारहीड प्रखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और भरोसे का माहौल बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत, एमएसीटी के 45 मामलों में 4.50 करोड़ का मुआवजा तय, ट्रैफिक चालान पर मिली भारी राहत



भागलपुर। भागलपुर व्यवहार न्यायालय सहित अनुमंडल न्यायालय नवगछिया और कहलागंज में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए हैं। अदालत में आपसी सहमति और सुलह–समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना दावा मामले में न्यायाधिकार के अध्यक्ष विजय कुमार की पीठ में विशेष सुनवाई के बाद 45 मामलों में बीमा कंपनियों और वाहन मालिकों की सहमति से कुल 4,50,20,000 (साढ़े चार करोड़ रुपये) के मुआवजे पर समझौता कराया गया। परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत वाहन स्वामियों के लिए जिला स्कूल परिसर में विशेष बेंच लगाई गई, जहां पुराने लंबित ई–चालानों का रियायती दरों पर निष्पादन किया गया। बैंक लोन रिकवरी, बिजली बिल बकाया और शमनीय अपराधिक मामलों में भी दोनों पक्षों की उपस्थिति से मामलों का ऑन–द–स्पॉट निस्तारण किया गया। वहीं न्यायालय परिसरों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष सहायता काउंटर, पेयजल और मेडिकल टीमों की पुख्ता व्यवस्था की गई थी, ताकि दूर–दराज से आने वाले वादकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

वरीय अधिवक्ता विंध्याचल राय बने अपर महाधिवक्ता, लोगों ने दी बधाई

बक्सर/डुमरांव। नगर के निशा नगर निवासी पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता विंध्याचल राय को राज्य का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में उच्च न्यायालय पटना में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों की कोटि में अपर महाधिवक्ता के पद पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन द्वारा की गई है। इसकी जानकारी मिलते ही डुमरांव नगर सहित उनके गृह विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुर में खुशियों की लहर दौड़ गई। वहीं उनके शुभचिंतकों एवं समर्थकों ने आपस में मिठाई बांटकर जमीन से जुड़े श्री राय के अपर महाधिवक्ता बनने की खुशियां मनाई। विदित हो की वरीय अधिवक्ता विंध्याचल राय डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड के जवही जगदीशपुर गांव के मूल निवासी हैं। जिन्होंने अपनी मेहनत व समर्पण के बल बकालत पेशे की शुरुआत अपने गृह जिले बक्सर से कर राज्य के वरीय अधिवक्ताओं में अपना नाम दर्ज कराया। संप्रति वे अभी भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी हैं। छत्र जीवन से सामाजिक सरोकार व राष्ट्रवादी छत्र संगठन एबीवीपी से जुड़े रहे विंध्याचल राय को राज्य के अपर महाधिवक्ता बनाए जाने पर विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों ने बधाई दी है। बधाई देने वालों में स्थानीय विधायक व जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राहुल कुमार सिंह, युवराज शिवांग विजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह भुवन, मानवाधिकार संरक्षण प्रतियन्ता के जिलाध्यक्ष रामबहादुर सिंह, शिक्षाविद डा. रमेश सिंह, समाजसेवी राजीव रंजन सिंह, भाजयुमो नेता व पूर्व वार्ड पार्षद सोनू राय, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष निहार रंजन, सुनील सिद्धार्थ, अजय प्रताप सिंह, नप के पूर्व उप चेयरमैन चुनमुन प्रसाद वर्मा, भाजपा जिला प्रवक्ता शक्ति राय, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार कुंवर, डुमरांव अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंदेव सिंह, सवित्र पृथ्वीनाथ शर्मा, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंदन सिंह, विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे, अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव, अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह छोटे, मो. इजहार सहित अन्य शामिल हैं।

गयाजी में 25 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला , 70 हजार श्रद्धालुओं के आवासन की तैयारी

पटना,एजेंसी। मोक्ष की भूमि गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से शुरू होगा। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करेंगे। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए पितृपक्ष मेला 16 दिनों का होगा, जबकि त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने वाले श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मेले को लेकर जिला प्रशासन करीब 70 हजार लोगों के ठहरने की क्षमता विकसित कर रहा है। पितृपक्ष मेले में श्रद्धालु अपनी सुविधा और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक, तीन, पांच, सात या नौ दिनों तक गयाजी में रहकर पिंडदान करते हैं। गयापाल पंडा एवं विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य मणिलाल बारिक के अनुसार, इस बार 25 सितंबर से पिंडदान और श्राद्ध का सिलसिला शुरू होगा। अलग–अलग तिथियों पर गयाजी के विभिन्न पिंडवेदी स्थलों पर निर्धारित कर्मकांड संपन्न होंगे। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने आवासन, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, परिवहन और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। पर्यटन विभाग की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए 2,500 बेड की क्षमता वाली टेंट सिटी, अस्थायी पर्यटक सुचना केंद्र और हेल्पलाइन की व्यवस्था की जा रही है।

अलग–अलग तिथियों पर निर्धारित हैं पिंडदान के कर्मकांड

25 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी के दिन पुनपुन में पिंडदान और गयापाल तीर्थपुरोहित की पांव पूजा का विधान है।26 सितंबर को फल्गु स्नान, श्राद्ध और पांव पूजा होगी।27 सितंबर को ब्रह्मकुंड में जी के चूर्ण से पिंडदान के साथ प्रेतशिला, रामशिला और रामकुंड में श्राद्ध तथा काकबली में पिंडदान किया जाएगा।28 सितंबर को पंचतीर्थ श्राद्ध के तहत उत्तरमानस, उदीची, कनखल, दक्षिणमानस और जिह्नलोल में कर्मकांड होगा।29 सितंबर को सरस्वती स्नान, पंचरत्न दान, मातंगवापी और धर्मारण्य कूप में श्राद्ध तथा बोधगया में बोधितरु दर्शन का विधान है।30 सितंबर को ब्रह्मसरोवर और काकबली श्राद्ध के साथ आग्रसिंचन में पिंडदान किया जाएगा।1 अक्टूबर को रुद्रपद, ब्रह्मपद और विष्णुपद में श्राद्ध होगा। इस दिन खीर और मावा के पिंड से पिंडदान तथा गयापाल तीर्थपुरोहित की पांव पूजा होगी।2 अक्टूबर को कार्तिकपद, दक्षिणाग्निपद और गार्हपत्याग्निपद श्राद्ध तथा 3 अक्टूबर को सूर्यपद,

प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम से बूथ स्तर तक कांग्रेस होगी और मजबूत : राजेश राम

पटना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘प्रशिक्षक–प्रशिक्षण शिविर’ का शुभारंभ शनिवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, सदाक़त आश्रम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर का उद्देश्य कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को वैचारिक एवं संगठनात्मक रूप से सशक्त बनाना तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की ऐसी मजबूत टीम तैयार करना है, जो आगे प्रखंड, पंचायत एवं बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करे। इस अवसर पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस का संगठन केवल पदाधिकारियों से नहीं, बल्कि समर्पित और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से मजबूत होता है। यह प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नई समझ और नई जिम्मेदारी का भाव पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की

विचारधारा और देश के संविधान की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन आवश्यक है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और विचारों को प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यह प्रशिक्षण शिविर उसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा, संगठन की कार्यप्रणाली और जनता के मुद्दों को समझकर पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जाए। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण और जनसेवा कांग्रेस की प्राथमिकता है। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम के माध्यम से कांग्रेस को गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

बक्सर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई ने हासिल किया वाणिज्यिक प्रचालन

बक्सर,एजेंसी। बक्सर जिले के चौसा में स्थापित 1320 मेगावाट क्षमता वाली बक्सर ताप विद्युत परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाई–2 ने 12 सितंबर 2026 को सफलतापूर्वक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया। इसके साथ ही परियोजना की दोनों इकाइयां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं और पूरी 1320 मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध हो गई है। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार, विद्युत मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रति मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और योगदान को भी सराहना की। इकाई–2 के वाणिज्यिक प्रचालन के साथ बक्सर ताप विद्युत परियोजना एसजेवीएन की पहली ताप विद्युत परियोजना बन गई है, जिसकी दोनों इकाइयां अब व्यावसायिक रूप से संचालित हैं। इस अवसर पर निदेशक (वािक्त) अजय कुमार शर्मा, निदेशक (मिफ्ट) पार्थजीत डे तथा निदेशक (परियोजनाएं) राजेश कुमार चंदेल ने भी कर्मचारियों एवं संबंधित हितधारकों को बधाई दी। बक्सर के चौसा में स्थित 2 गुना 660 मेगावाट क्षमता की बक्सर ताप



चंद्रपद, गणेशपद, संध्याग्निपद, आवसंध्यग्निपद और दधीचीपद में श्राद्ध किया जाएगा। 4 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी के अवसर पर कवचपद, मातंगपद, क्रौंचपद, अगस्त्यपद, इन्द्रपद, कश्यपपद और गजकर्णपद में श्राद्ध होगा। सीताकुंड में बालू से पिंडदान, रामगया श्राद्ध, दूध तर्पण और अनन्दान का भी विधान है। 5 अक्टूबर को गयासिर और गयाकूप में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाएगा, जिसे पितृदोष और प्रेतदोष निवारण से जुड़ा कर्मकांड माना जाता है। 6 अक्टूबर को मुण्डपृष्ठा, आदि गदाधर और धौतपद में श्राद्ध होगा।7 अक्टूबर को भीमगया, गौप्रचार और गदालोल श्राद्ध, जबकि 8 अक्टूबर को भगवान विष्णु का पंचामृत स्नान–पूजन और फल्गु में दुग्ध तर्पण किया जाएगा।9 अक्टूबर को वैतरणी सरोवर पर गोदान और तर्पण तथा 10 अक्टूबर को अमावस्या के दिन अक्षयवट में श्राद्ध, खीर से पिंडदान, सुफल और पितृ विसर्जन का विधान है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने वालों के लिए 11 अक्टूबर को गायत्री घाट पर दही–चावल से पिंडदान, आचार्य को दक्षिणा और पितृ विदाई का कर्मकांड होगा।

70 हजार लोगों के आवासन की तैयारी

श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन करीब 70 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर रहा है। गांधी मैदान में 2,500 बेड की टेंट सिटी तैयार की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

बाइक सवार तीन अपराधियों ने व्यापारी को घेरा, 35 हजार लूटे, विरोध पर चलाई गोलीं

सुपौल,एजेंसी। जिले के जदिया थाना क्षेत्र

के रानीगंज–त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग स्थित तमकुलहा पुल के समीप एनएच–327ई पर शनिवार को दिनदहाड़े पल्सर बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने दो मवेशी व्यापारियों को घेरकर 35 हजार रुपये लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चला दी। गोली एक व्यापारी की कमर को छूते हुए निकल गई, जिससे वह जखमी हो गया। घटना के बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई लूट और गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

घायल व्यापारी की पहचान मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के कुमारखंड वार्ड संख्या सात निवासी इस्लाम खान के पुत्र सोनू खान (20) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल सोनू को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल सोनू खान ने बताया कि वह अपने साथी व्यापारी मोहम्मद खुशींद आलम के साथ बघला से बकरी बेचकर एक ही बाइक से अपने घर कुमारखंड लौट रहा था। इसी दौरान तमकुलहा पुल के समीप पीछे से पल्सर बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक को घेर लिया। अपराधियों ने



हथियार के बल पर दोनों से रुपये छीनने शुरू कर दिए। सोनू ने बताया कि उसने लूटपाट का विरोध किया तो अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसकी कमर को छूते हुए निकल गई। इसके बाद अपराधी उसके पास से 30 हजार रुपये और बाइक पर पीछे बैठे दूसरे व्यापारी खुशींद आलम के पास से पांच हजार रुपये लेकर फरार हो गए। अस्पताल की चिकित्सक डॉ. प्राची कश्यप ने बताया कि घायल को रोड रॉबरी की घटना के समाधान लाया गया है। उसकी कमर पर गहरा जख्म है। जख्म को देखने से प्रतीत होता है कि गोली कमर को छूते हुए निकली है। फिलहाल घायल का

इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि 35 हजार रुपये की लूट हुई है और गोली भी चली है। मामले की जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संधावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

लोक अदालत में 190 चालानों के निष्पादन में जमा हुए 6 लाख 10 हजार की राशि

अररिया। अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित 190 ट्रैफिक चालानों का निष्पादन में 6 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की गई।लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन चालानों के निष्पादन को लेकर वाहन स्वामियों की अच्छी–खासी भीड़ जुटी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से संबंधित लंबित ई–चालानों के समाधान के लिए लोक अदालत पहुंचने लगे। दिनभर आयोजन स्थल पर वाहन स्वामियों की आवाजाही बनी रही तथा देर शाम तक चालान निष्पादन का कार्य जारी रहा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत आयोजित इस विशेष अभियान में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पात्र चालानों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई। पात्र मामलों में शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने के प्रावधान के कारण वाहन स्वामियों में अपने पुराने चालानों का समाधान कराने को लेकर विशेष रुचि देखने को मिली।

लोक अदालत परिसर में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए चालान सत्यापन, निष्पादन, भुगतान एवं तकनीकी सहायता से संबंधित अलग–अलग काउंटर बनाए गए थे। अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों के चालानों की जांच कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहने से वाहन स्वामियों को भुगतान में भी सहूलियत हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला



एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न काउंटरो पर जाकर चालान निष्पादन की प्रक्रिया तथा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बताया। वहीं जिला पदाधिकारी विनोद दूहन के दिशा निर्देश में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लोक अदालत में आने वाले वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं व्यवस्थित सुनिश्चित की गई थी।

एक नजर

इंडोनेशिया में 6.6 तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत नहीं



जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशिया के उत्तर-पूर्वी जावा प्रांत में शुक्रवार तड़के 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र तेलुक्नागा के पास था, और यह स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 4:23 बजे आया। तुर्किया की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू व अन्य मीडिया ने यूएसजीएस के हवाले से बताया कि भूकंप जमीन के नीचे करीब 358.6 किलोमीटर की गहराई में आया। इतनी अधिक गहराई पर आए भूकंप के बावजूद तत्काल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली। स्थानीय अधिकारियों की ओर से भी किसी बड़े ढांचागत नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण भूकंप और ज्वलामुखी गतिविधियां आम हैं। फिलहाल, अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी संभावित नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है।

सऊदी अरब ने कच्चे तेल की पाइपलाइन

'ईस्ट-वेस्ट' को बंद करने का किया ऐलान



रियाद। सऊदी अरब ने अपनी रणनीतिक 'ईस्ट-वेस्ट' कच्चे तेल की पाइपलाइन को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, इस पाइपलाइन को एक दिन पहले रियाद और मक्का क्षेत्रों में कई हमलों का निशाना बनाया गया था। हालांकि, मंत्रालय ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं बताई है और न ही पाइपलाइन को हुए नुकसान की जानकारी दी है। ईरान सरकार का अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के अनुसार, 'ईस्ट-वेस्ट' पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। यह देश के तेल क्षेत्रों की लाल सागर स्थित निर्यात टर्मिनलों से जोड़ती है और फारस की खाड़ी से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है। होमुजु जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने के बाद इस पाइपलाइन की रणनीतिक अमरियत और बढ़ गई है। सऊदी अरब को के सीईओ अमीन नासिर ने पिछले महीने कहा था कि होमुजु जलडमरूमध्य के बंद होने के प्रभाव को कम करने में इस पाइपलाइन ने आपातकालीन तेल भंडार जारी करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सऊदी अरब के लाल सागर स्थित तेल निर्यात मार्ग पर भी दबाव बढ़ रहा है। यमन की ओर से सऊदी तेल टिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों और समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद क्षेत्र में तेल परिवहन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि, जुलाई में यमन की सेना ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा करते हुए इसे 'घेरावों के बदले घेरावों' की रणनीति बताया था। जहाजों की आवाजाहारी पर नजर रखने वाले आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में लाल सागर के रास्ते सऊदी तेल के प्रवाह में भारी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी शहर यानबू से सऊदी कच्चे तेल और कंडेनसेट की लॉडिंग प्लेट महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। वहीं, मार्केट इंटीलेंस बैलेंस (टेडफॉर्म वॉर्टेक्स) ने अगस्त में यानबू से लॉडिंग करीब 32 लाख बैरल प्रतिदिन आंकी, जबकि केप्टर के आंकड़ों के मुताबिक यह लगभग 15 लाख बैरल प्रतिदिन रही। पाइपलाइन बंद करने का फैसला ऐसे समय में आया है जब सऊदी अरब के कच्चे तेल उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोवेलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के अनुसार, अगस्त में सऊदी अरब का तेल उत्पादन घटकर करीब 62.4 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि जुलाई में यह लगभग 81 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह 1990 के बाद सऊदी तेल उत्पादन का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। यह गिरावट ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब और ओपेक के अन्य देश तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ रहे थे। क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी के कारण तेल बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जबकि साहारा के अंत तक तेल की कीमतों में 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई। यदि सऊदी अरब के वैकल्पिक तेल निर्यात मार्ग भी लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।

इज़राइल-लेबनान वार्ता का अगला दौर

वाशिंगटन में, रोम की बैठक अक्टूबर तक टली

वाशिंगटन। इजराइल-लेबनान के बीच जारी बातचीत के अगले दौर की तारीख और जगह में बदलाव किया गया है। रोम में अगले हफ्ते होने वाली बैठक अब अक्टूबर तक टाल दी गई है, जबकि दोनों देशों के राजदूत वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में जून के फ्रेमवर्क समझौते को लागू करने और इजराइली सेना को लेबनान से वापसी पर चर्चा होगी। तुर्किए की सरकार समचार एजेंसी अनाडोलू ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि बैठक में जून में हुए समझौते से जुड़े घटनाक्रम और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। औपचारिक वार्ता का अगला दौर अब अक्टूबर में रोम में होने की संभावना है। वहीं, इस मामले में एक सूत्र के मुताबिक, यहूदी धार्मिक छुट्टियों, लेबनानी सशस्त्र बलों के समर्थन में होने वाले पेरिस कांग्रेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा की तैयारियों के कारण प्रमुख प्रतिभागियों का अगले सप्ताह रोम में जुटना संभव नहीं था। वहीं, बैठक की योजना में बदलाव को लेकर अभी इजराइल या लेबनान की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। इजराइल और लेबनान के बीच अप्रैल से अब तक सीधे बातचीत के सात दौर हो चुके हैं। इनमें पांच बैठकें वाशिंगटन और दो रोम में हुईं।

उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, दक्षिण कोरिया ने बढ़ाई निगरानी

सियोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया ने शनिवार सुबह ईस्ट सी (पूर्वी सागर) की ओर कई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाँगीं। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक, यह लॉन्च दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच पाँच दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'फ़्रीडम एज' के समाप्त होने के एक दिन बाद हुआ। दक्षिण कोरिया की सरकारों समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक दक्षिण कोरिया के जॉर्डे चीम्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने बताया कि सुबह करीब 5:20 बजे उत्तर कोरिया के वोनसन इलाके से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का पता चला। मिसाइलें समुद्र में गिरने से पहले करीब 250 किलोमीटर तक उठीं।

जैसेएस ने कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ उत्तर कोरिया की सैन्य विधिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। मिसाइल लॉन्च से जुड़ी जानकारी जापान के साथ भी साझा की गई है। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा, 'हमारी सेना दक्षिण कोरिया-अमेरिका की मजबूत रक्षा स्थिति के तहत उत्तर कोरिया की विभिन्न विधिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है और किसी भी उकसावे का करारा जवाब देने की क्षमता और तैयारी बनाए हुए है। दक्षिण कोरियाई सैन्य स्रोतों के मुताबिक, शुरुआती आकलन में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कोरिया ने कई बार ह्रासों-11 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों और 600 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से गोले दागे। जेसीएस ने संभावित अतिरिक्त मिसाइल लॉन्च को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है और दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा जापान के बीच सूचना साझा करने के साथ सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश

दिया है। यह मिसाइल पड़ोशन दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त 'प्रीडम एज' सैन्य अभ्यास के ठीक बाद हुआ। पांच दिवसीय यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजु के पूर्व और दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में आयोजित किया गया था। अभ्यास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हुआ। इससे पहले सियोल और वाशिंगटन ने अपना वार्षिक संयुक्त 'रुबिनी प्रीडम शील्ड' (UFS) अभ्यास कम स्तर पर आयोजित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने दक्षिण कोरिया-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों में कटौती का आदेश दिया था। ट्रंप ने इन अभ्यासों को महंगा बताते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया के लिए ये गतिविधियाँ अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत देती हैं। मिसाइल लॉन्च से कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री किम सोंग-गन ने तीन देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों

आलातना की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी उत्तर कोरिया के साथ नया सैन्य टक्कर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो प्योंगयांग अपनी ताकत के दम पर कड़ जवाबी कदम उठाएगा। उत्तर कोरिया लंबे समय से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। प्योंगयांग इन अभ्यासों को सभाविक्त हमले की तैयारी के तौर पर देखता है और अक्सर इनके विरोध में मिसाइल व अन्य हथियारों के परीक्षण करता है। शनिवार को मिसाइल परिक्षण ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने के अंत में वाशिंगटन में अहम बैठक होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि दोनों नेताओं की बैठक के एजेंडे में उत्तर कोरिया और कोरियाई प्राद्वीप की सुझा स्थिति से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।

नेपाल : अपर त्रिशली-१ हाइड्रोपावर परियोजना

में 17 दिनों के उत्खनन के बाद बाद 7 शव मिले

काठमांडू। नेपाल में बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त 216 मेगावाट की अपर त्रिशुली-1 जलविद्युत परियोजना में 17 दिनों के लगातार प्रयास के बाद सत लोगों के लगे बरामद किए गए हैं। सुरंग और हेडवर्क्स क्षेत्र में लापता लोगों की तलाश के दौरान शुक्रवार देर रात तक शव मिले। इसकी जानकारी स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (आईपीपीएन) ने दी है। बताया गया है कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से परियोजना में बड़ी संख्या में कर्मचारी और श्रमिक लापता हैं। शुक्रवार को नेपाली सेना और परियोजना की प्रवर्द्धक कंपनी नेवाटर एअर एंजनी डेवलपमेंट कंपनी के सर्वे इंजीनियरों समेत एक संयुक्त टीम ने आईड-1 क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरंग का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे से भर पला, जिससे अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ है।

वहीं, मैलुंग कैप साइट पर मिनी स्कावेटर की मदद से खुदाई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर, ऑडिट-3 क्षेत्र में नेपाली सेना और ऑस्ट्रेलियाई बचाव दल ने भी तलाशी अभियान चलाया। परियोजना प्रबंधन ने कहा है कि शनिवार से लापता लोगों की



तलाश और बचाव अभियान का
और तेज किया जाएगा। बाढ़ आने
से पहले परियोजना स्थल पर कुल
1,433 लोग काम कर रहे थे। इनमें
से अब तक 878 लोगों को सुरक्षित
बहाल निकाला जा चुका है, जबकि
595 लोग अभी भी लापता हैं। सात
शवों की बरामदगी के बाद
परियोजना में लापता लोगों के
परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।
देहाव दल फिंतालहल सुरंगों
हडबक्स और कैप साइड के
विभिन्न हिस्सों में मलबा हटाने
लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।
लगातार मलबा, पानी और कटिंग
भौगोलिक परिस्थितियां राहत एजेंसी
खोज अभियान के सामने बड़ी
चुनौती बनी हुई हैं।

यमन की सेना का दावा- लाल सागर तट के बड़े इलाके पर कब्जा, सैकड़ों सऊदी समर्थित लड़ाके मारे गए

A man in a military uniform and red beret is speaking at a press conference. He is wearing glasses and has a mustache. Several microphones are in front of him, including one with the Arabic text 'إلى أين' (Where to) and another with 'إلى أين' (Where to). The background is blurred, showing a large emblem.

सना,एजेंसी। यमन में सऊदी अरब के खिलाफ सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। यमनी सेना के प्रवक्ता रिगिडियर जनरल याह्या सरी ने दावा किया है कि सेना ने हुदुदह और ताइज प्रांतों में करीब 5,400 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और सैकड़ों सऊदी समर्थित लड़कों को मार गिराया जा घायल किया है। प्रवक्ता ने बाब अल-मदाब की ओर बढ़ने और सऊदी ठिकानों के खिलाफ हमले तेज करने की भी चेतावनी दी है।

ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के मुताबिक शुक्रवार को

टेलीविजन पर दिए बयान में सरी ने कहा कि यमनी सेना और 'पापुलर कमिटीयों' से जुड़े लड़ाकों ने दोनों प्रांतों के छह जिलों से सऊदी समर्थित बलों को खदेड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि अभियान के दौरान सऊदी समर्थित लड़ाकों की सात हिवोजनों और 38 ब्रिगेड को पराजित किया गया।

सरी के अनुसार, लड़ाई में 'सैकड़ों' लड़ाके मारे गए या घायल हुए, जबकि कई अन्य को हिरासत में लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सैन्य बलों ने उन कई कैदियों को मुक्त कराया, जिन्हें कथित तौर पर सऊदी समर्थित बलों द्वारा

संचालित हिरासत केंद्रों में रखा गया था। यमनी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने 32 अभियान चलाए और सऊदी विमानों की घुसपैठ को रोकते हुए नौ विमानों को मार गिराया। हालाँकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि का तत्काल कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सरी ने कहा कि यमनी सेना लाल सागर में जहाजों की आवाजाही को लेकर अपनी घोषित नीति पर कायम है। उनके मुताबिक, सऊदी अरब से आने वाले जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों के लिए लाल सागर से गुजरने की अनुमति रहेगी। उन्होंने इसे 'घेराबंदी के बदले घेराबंदी' की नीति बताते हुए कहा कि जब तक यमन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी जारी रहेगी, सऊदी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहेगा। यमन में संघर्ष वर्ष 2015 में उस समय तेज हुआ, जब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमनी सरकार के समर्थन में सैन्य अभियान शुरू किया। संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और देश गंभीर मानवीय संकट से जूझता रहा है। यमनी सेना के प्रवक्ता के ताजा दावों के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ने का भी आशंका नहीं हुई है। हुदुदाह और बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लाल सागर के जरिए अंतराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है।

यूएन महासभा में जलवायु न्याय और मुआवजे के लिए पांच मद्दे उठाएंगे पीएम बालेन्द्र शाह

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के मुआवज का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी में हैं। न्यूयॉर्क में आगामी 24 सितंबर को महासभा को संबोधित कर रहे हुए प्रधानमंत्री शाह जलवायु न्याय और क्षतिपूर्ति से जुड़े पांच प्रमुख एजेंडे प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे, जबकि उनसे पहले विदेश मंत्री शिशिर खनाल 20 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे।

विदेश सचिव अमृत बहादुर राई के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगी कि जलवायु परिवर्तन और इससे पैदा होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण नेपाल को बार-बार बड़े पैमाने पर जनधन के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल का कार्बन उत्सर्जन बेहद कम होने के बावजूद वह जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभाव झेल रहा है। प्रधानमंत्री वैश्विक समुदाय से जलवायु न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान करेंगे। नेपाल इस बात पर जोर देगा कि जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए उसे तत्काल और उचित क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। नेपाल सरकार पहले ही जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग कर चुकी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस मांग पर लॉस एंड डैमेज फंड की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसके अलावा नेपाल विकसित और समृद्ध

देशों से जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण, क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने और संबंधित पक्षों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीक तथा जलवायु चिन्ता को आसान और रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराने की अपील करेगा। नेपाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पार्यवारण संरक्षण में अपने योगदान को भी प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रकृति के अनुकूल जीवाणुशैली, 46 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र, विशाल हिमालयी क्षेत्र और व्यापक नदी प्रणाली के जरिए वैश्विक पार्यवारण संरक्षण में नेपाल की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। विदेश सचिव अमर बहादुर राई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा नेपाल के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पिछले वर्ष के जेन-जी आंदोलन के सफल बाद हुए सफल चुनाव और बड़े जनश्रेश के साथ बनी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं को रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही नेपाल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना को जारी रखने तथा उसे और बढ़ाने का आह्वान भी करेगा। महासभा के दौरान नेपाल 'सगरमाथा' से समुद्र तक : जलवायु उत्थानशील भविष्य के लिए आह्वान' शीर्षक से एक अलग बैठक भी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण खसकर हिमालयी क्षेत्रों पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव और उससे पैदा होने वाली विनाशकारी परिस्थितियों पर चर्चा करना तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच इस गंभीर संकट की ओर आकर्षित करना होगा।

बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी सेना पर दो हमले, कई जवानों के मारे जाने की खबर

बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले तेज होने की खबर है। सुराब जिले में शुक्रवार को सेना को निशाना बनाकर दो अलग-अलग हमले किए जाने का दावा किया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पहले हमले में कई सैनिकों के मारे जाने और एक सैन्य वाहन के नष्ट होने की खबर है। इसके बाद मारे गए जवानों के शव लेने पहुंची सैनिकों की दूसरी टीम पर भी हमला किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, इन घटनाओं में हताहतों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

बलूचिस्तान के आनलाइन अनुसार, पहले एक धमका हुआ और उसके बाद हथियारबंद लोगों ने सेना के काफिले पर नाके लगाकर हमला किया। विस्फोट और गोलीबारी में सेना को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। लेकिन हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं मिली। धमके में इलाके का एक पुल भी क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई है। इस घटना की भी पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस दौरान चगाई जिले के चेहाटर इलाके में एक व्यापारिक मार्ग पर हथियारबंद लोगों द्वारा नाकेबंदी किए जाने की खबर है।



शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराई ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन से 23 शैक्षणिक संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 25 स्कूलों का इस्तेमाल विस्थापित नागरिकों के आश्रय स्थल के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में तत्काल पढ़ाई शुरू करने की स्थिति नहीं है। विस्थापितों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय शुरू कर दिया गया है। तीनों जिलों में सबसे ज्यादा शैक्षिक नुकसान नुकावोट में हुआ है। यहां 11 स्कूल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 16 स्कूलों को होर्डिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य स्कूल में भवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण पढ़ाई शुरू

हो सकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोट में कुल 6,315 विद्यार्थियों की प्रवृत्ति प्रभावित हुई है। इसी तरह धादिंग में आठ स्कूलों में से शक्तिप्रस्त हुए हैं, जबकि दो स्कूलों को लंदन से भर्त बनाया गया है। चार अन्य स्कूलों के लिए तैयार हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लान नहीं पहुंचने के कारण वहां भी कक्षाएं शुरू हो सकी हैं। धादिंग में इन सभी प्रभावित स्कूलों में कुल 5,066 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। जब जिले में चार स्कूल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तब सात स्कूलों में विस्थापित लोगों को खाना पकाया है। इसके अलावा 10 अन्य स्कूलों में भी विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, कुल मिलाकर रसुमा में 3,074 विद्यार्थियों की प्रवृत्ति प्रभावित हुई है।

एक नजर

हिंदी देश को जोड़ने वाली सशक्त
भाषा : महेश कुमार गौड़

हैदराबाद,एजेंसी। हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी के विकास के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य बी. महेश कुमार गौड़ ने शनिवार को यह बात कही। बशीरबाग स्थित प्रेस क्लब, देशोद्धारक भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस भाषाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में तथा हैदराबाद हिंदी जर्नलिस्ट्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में श्री गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से लगाव होता है और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “तेलुगु मेरी मातृभाषा है। हमें तेलुगु के विकास के साथ-साथ हिंदी के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। श्री गौड़ ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि दक्षिण भारत के सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हिंदी में अपनी बात रखें, ताकि देश के अधिक से अधिक नागरिकों तक उनकी बात पहुंच सके। उन्होंने कहा कि देश में हिंदी का पठन-पाठन लगातार कम होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। हिंदी को विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में स्थान दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से हिंदी पढ़ने-लिखने का आग्रह करते हुए कहा कि हिंदी के ज्ञान से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। तेलंगाना सरकार के सलाहकार एवं पूर्व सांसद वी. हनुमंत राव ने कहा कि हिंदी दिवस सभी के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में करीब दो सौ वर्षों से हिंदी भाषी लोग रह रहे हैं और प्रदेश के विकास में रचनात्मक योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर बस रहे हैं। बेहतर मौसम और कानून-व्यवस्था के कारण तेलंगाना तेजी से आकर्षण का केंद्र बन रहा है। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के साथ ही हिंदी पत्रकारों और हिंदी पत्रकारिता के विकास के लिए सरकार से सहयोग की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। पूर्व विधायक एवं भू-भारती के अध्यक्ष एम. कोटंडा रेड्डी ने कहा कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव एवं तेलंगाना कांग्रेस के सह प्रभारी सचिन सावंत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदी को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदी को इसलिए बढ़ावा देते थे, ताकि शासन और जनता के बीच दूरी कम हो। श्री सावंत ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में भाषाई अल्पसंख्यक समितियों का गठन किया है। उन्होंने अनुभव सांगया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भाषा और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के आयोजक एवं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस भाषाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन राजेश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। करोड़ों लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का हिंदी एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवेंट रेड्डी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। समारोह में हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न स्मारक पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वर्गीय विनयवीर स्मारक पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार एवं समीक्षक डॉ. ऋषभदेव शर्मा, स्वर्गीय सदाशिव शर्मा पत्रकार स्मारक पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार डॉ. देवकुमार पुखराज तथा स्वर्गीय विद्यारण्य हरिबेल्ले के पत्रकार स्मारक पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि मनोज कोसंरकर को प्रदान किया गया। इसके अलावा हिंदी के क्षेत्र में सक्रिय समाजसेवियों, पत्रकारों, शिक्षकों, लेखकों और कवियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह की खस बात यह रही कि हिंदी शिक्षकों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों तथा स्कूली बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

‘विघ्नहर्ता से विकासकर्ता’ की थीम पर सजेगा गणेश महोत्सव का पंडाल

नई दिल्ली,एजेंसी। राजधानी में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। गणपति महोत्सव को लेकर आयोजक कई नई आकर्षक चीजें लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मी नगर स्थित श्री गणेश सेवा मंडल, दिल्ली (रजि.) इस बारे भव्य आयोजन के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाले हैं। 14 से 25 सितंबर तक लक्ष्मी नगर के प्रियदर्शनी बिहार स्थित डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम, बैंक एनक्लेव में आयोजित होने वाले गणपति उत्सव की थीम ‘विघ्नहर्ता से विकासकर्ता—25 वर्ष की आस्था, 2047 विकसित आधुनिक भारत का संकल्प’ रखी गई है। पत्रकार के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र लड्डु ने संस्कार वार्ता में बताया कि संस्था पिछले 25 वर्षों से लक्ष्मी नगर में ‘दिल्ली का महाराजा’ के नाम से गणेश महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। यह साल हमारे गणपति बप्पा दिल्ली का महाराजा का 25वां गणेश महोत्सव है जिसे हम खास एवं यादगार बनाना चाहते हैं घ सिल्वर जुबली वर्ष को विशेष बनाने के लिए इस बार भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत तक की विकास यात्रा को गणेश महोत्सव की थीम से जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि इस बार ‘विघ्नहर्ता से विकासकर्ता’ की विशेष अवधारणा के तहत दिल्ली का महाराजा गणपति के हाथों में मेड इन इंडिया ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल एवं सेमीकंडक्टर प्रदर्शित किए जाएंगे। यह प्रस्तुति आध्यात्मिक आस्था के साथ भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी एवं रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगी। उत्सव स्थल पर गणपति बप्पा दिल्ली के



महाराजा के भव्य मंगल मूर्ति के साथ इस बार लक्ष्मी माता की 5 फुट की मूर्ति एवं संत मंच पर विठ्ठल भगवान की 6 फुट की मूर्ति,

रविमणी माता की 5 फुट की मूर्ति एवं संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम एवं खादू श्याम महाराज

हृदय रोगियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, इलाज के बाद जल्द सामान्य जीवन में लौटने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली,एजेंसी। हृदय रोगियों को इलाज के बाद बेहतर तरीके से स्वस्थ करने के लिए वर्धमान मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसका मकसद हृदय रोगियों को बीमारी के बाद दोबारा सामान्य जीवन जीने में मदद करना है। इसमें मरीज के व्यायाम, खान-पान, मानसिक स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जीवनशैली पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन जारी करने के लिए शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जाने-माने वैज्ञानिक और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. निर्मल कुमार गांगुली मुख्य अतिथि रहे। डॉ. हर्षवर्धन और डॉ. विजय मोहन कोहली विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन-एईएसएआरओ की क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. ताशी टोबेगे समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर और विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। डॉ. निर्मल कुमार गांगुली ने देश में बढ़ती हृदय संबंधी बीमारियों को देखते हुए ऐसी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तैयार की गई इस गाइडलाइन की सराहना की। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, नई गाइडलाइन से हृदय रोगियों की देखभाल में एकरूपता आएगी। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को बीमारी के बाद अपनी शारीरिक क्षमता वापस पाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिल की बीमारी से ठीक होने के बाद केवल दवा लेना ही



पर्याप्त नहीं है। मरीज को सही व्यायाम, बेहतर खान-पान, तनाव कम करने और जीवनशैली में बदलाव की भी जरूरत होती है।

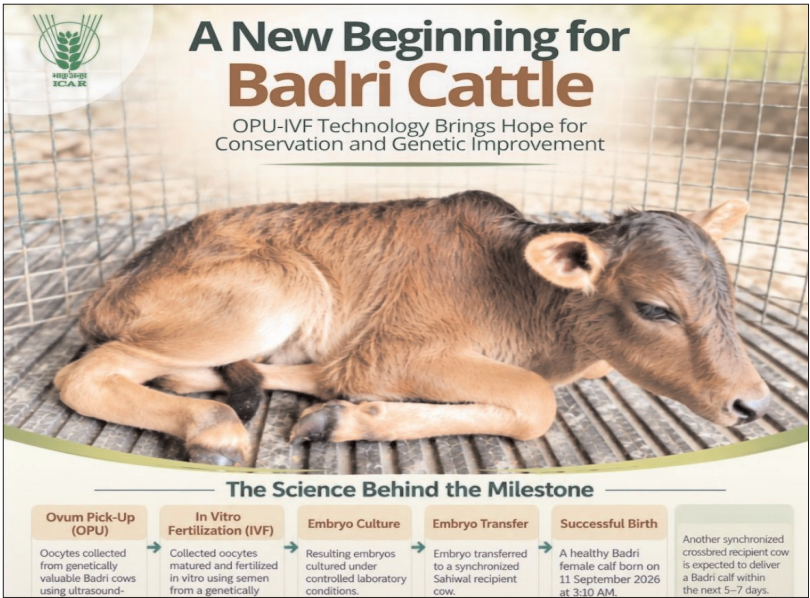
इसी को ध्यान में रखते हुए कार्डियक रिहैबिलिटेशन यानी हृदय रोग के बाद शरीर को दोबारा मजबूत बनाने की प्रक्रिया के लिए यह गाइडलाइन तैयार की गई है। गाइडलाइन तैयार करने वाली टीम की प्रमुख सदस्य डॉ. सुमन बादल ने बताया कि इसे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देश में अस्पतालों की सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता तथा मरीजों की जागरूकता में अंतर को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। इस गाइडलाइन में कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन,

मनोवैज्ञानिक, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को मिलकर मरीज की देखभाल करने पर जोर दिया गया है। मरीज की स्थिति के अनुसार व्यायाम कराने, खान-पान सुधारने, मानसिक सहयोग देने और भविष्य में बीमारी से बचाव के उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर दिशा-निर्देश विकास समिति के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में हृदय रोगियों के पुनर्वास के लिए एक आसान, व्यवस्थित और व्यापक व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक जैसे चिकित्सकीय दिशा-निर्देश होने से मरीजों को बेहतर और समान स्तर की पुनर्वास सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही, हृदय रोगों के इलाज में पुनर्वास को और अधिक प्रभावी तरीके से शामिल किया जा सकेगा।

उत्तराखंड की स्वदेशी बंदी गाय के संरक्षण में बड़ी उपलब्धि, आईवीएफ के जरिए हुआ बछिया का जन्म

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तराखंड की स्वदेशी बंदी गाय के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्नत प्रजनन तकनीक ओवम पिक-अप और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के जरिए एक स्वस्थ बंदी नरस्त्री की बछिया का जन्म हुआ है। यह बछिया 11 सितंबर 2026 को अकादमिक डेयरी फार्म में पैदा हुई। इस उपलब्धि को खास बात यह है कि बंदी गाय के भ्रूण को साहीवाल गाय में प्रत्यारोपित किया गया था। सफल भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद साहीवाल गाय ने स्वस्थ बंदी बछिया को जन्म दिया।

बंदी गाय उत्तराखंड का राज्य पशु है और राज्य की महत्वपूर्ण स्वदेशी पशु आनुवंशिक संपदा मानी जाती है। यह प्रयोग आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के सहयोग से किया गया। परियोजना को उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, हल्दी से वित्तीय सहयोग मिला। आईसीएआर-एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने शनिवार को एक बयान में कहा कि ओपीयू-आईवीएफ जैसी उन्नत प्रजनन तकनीक से आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ मादा पशुओं से बड़ी संख्या में भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं। इससे बंदी नरस्त्री के उच्च जर्मप्लाज्म को पारंपरिक प्रजनन की तुलना में तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस शोध कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2023 में जीबी पंत विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. एमएस चौहान की पहल और नेतृत्व में हुई थी। इसके बाद पंतनगर विश्वविद्यालय और आईसीएआर-एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने बंदी गाय के लिए ओपीयू-आईवीएफ, भ्रूण उत्पादन और भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक विकसित करने पर काम किया। कार्यक्रम के तहत आनुवंशिक रूप से



मूल्यवान बंदी गायों से अल्ट्रासाउंड की मदद से अंडाणु निकाले गए। इन अंडाणुओं को प्रयोगशाला में परिपक्व किया गया और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड से प्राप्त आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ बंदी सांड के वीर्य से उनका निषेचन कराया गया।

तैयार भ्रूणों को नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में विकसित करने के बाद उपयुक्त समय के लिए तैयार की गई साहीवाल और अन्य गायों में प्रत्यारोपित किया गया। इसी प्रक्रिया से एक साहीवाल रिसिपिएंट गाय ने स्वस्थ बंदी बछिया को जन्म दिया। वैज्ञानिक टीम के अनुसार, एक अन्य तैयार क्रॉसब्रेड रिसिपिएंट गाय के भी अगले 5 से 7 दिनों में बंदी बछड़े को जन्म देने की उम्मीद है। बंदी नरस्त्री के संरक्षण और आनुवंशिक

सुधार के लिए वैज्ञानिक अब श्रेष्ठ और अधिक उत्पादन देने वाली बंदी गायों की क्लोनिंग पर भी काम कर रहे हैं। शोध के दौरान क्लोन किए गए बंदी भ्रूण तैयार करने में सफलता मिली है। अगले चरण में ओपीयू-आईवीएफ और क्लोनिंग से तैयार भ्रूणों को साहीवाल, क्रॉसब्रेड और बंदी नरस्त्री की उपयुक्त रिसिपिएंट गायों में प्रत्यारोपित करने की योजना है। इसका उद्देश्य श्रेष्ठ बंदी जर्मप्लाज्म का तेजी से विस्तार करना और इस स्वदेशी नरस्त्री के दीर्घकालिक संरक्षण एवं आनुवंशिक सुधार को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक प्रजनन तकनीक और देशी आनुवंशिक संसाधनों के इस संयोजन से हिमालयी क्षेत्र में टिकाऊ पशुधन विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

माई आनंद के बेटों को बसपा में रहकर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा: मायावती

लखनऊ,एजेंसी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह मेरा अंतिम फैसला और प्रतिज्ञा है कि भाई आनंद कुमार के किसी भी बेटे को बसपा में किसी भी छोटे-बड़े पद पर बने रहकर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जायेगा। जरूरत पड़ी तो वह आनंद की बेटों को मौका दे सकती हैं, जो अभी वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है। उन्होंने पार्टी के संस्थापक काशीराम का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भी अपने किसी भी परिवारवाद के खिलाफ डटी रहूंगी।

उन्होंने कहा कि मैं अविवाहित हूं। महिला हूं, इसलिए मजबूरी में अपने छोटे भाई आनंद को अपने साथ रखना पड़ा। वह मेरी देखभाल करने के साथ-साथ मेरी पूरम निगरानी में पार्टी की अहम जिम्मेदारियों को भी काफी लम्बे समय से निभा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ अब उनके परिवार के लोग भी



उठायें तो यह पार्टी व मूवमेंट के हित में सही नहीं होगा। इसीलिए आज मेरा अन्तिम यही फैसला व प्रतिज्ञा भी है कि इसके एवज में, अब इनके खासकर किसी भी बेटे को बसपा में किसी भी छोटे-बड़े पद पर बने रहकर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जायेगा। यदि आगे चलकर मेरे साथ रहते हयें आनन्द कुमार को मेरी मदद के लिए किसी और सदस्य की भी जरूरत पड़ती है तो फिर वह वर्तमान राजनैतिक हालात में केवल अपनी इकलौती बेटे कुमार दीपिका आनन्द को, जो इस समय वकालत की पढ़ाई कर रही है, उसे आगे चलकर उसकी मदद ले सकते हैं। उसकी ईमानदारी, वफादारी व कार्य

क्षमता आदि को देखकर पार्टी में उसे जरूरतानुसार अपनी खुद की जिम्मेवारी भी सौंप सकते हैं। लेकिन वे अपने दोनों बेटों को व आगे चलकर उनके युवा बच्चों में से किसी को भी अपनी यह जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे।

साथ ही, यह भी कहना है कि अपनी बेटों के तैयार नहीं होने पर फिर वे पार्टी की आम सहमति से केवल पार्टी के दलित वर्ग में से ही अन्य किसी मिशनरी कार्यकर्ता को भी अपनी यह जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। यही वर्तमान में समय की जरूरत है व पार्टी के हित में भी है। मायावती ने कहा कि इसी प्रकार पार्टी संगठन में व आगे सकार बनने पर भी, चाहे वह कोई भी हो, केवल सम्बन्धित उसी एक व्यक्ति को ही मौका दिया जायेगा, लेकिन उसकी आड़ में उसके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को कोई भी लाभ आदि नहीं दिया जायेगा, ताकि बसपा अब आगे परिवारवाद से मुक्त रहे तथा सर्वसमाज में से ज्यादा से ज्यादा लोग ‘सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति’ आन्दोलन के सहभागी बन सकें, जो कि अम्बेडकरवादी राजनीति के लिये बहुत जरूरी है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)

